



# फेसिलिटेटर की प्रशिक्षण नियमावली

ग्राम पंचायत विकास योजना  
'सबकी योजना सबका विकास'  
2 अक्टूबर - 31 दिसंबर 2018



राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडीपीआर)  
हैदराबाद

के द्वारा तैयार किया गया

पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर) और ग्रामीण विकास मंत्रालय  
(एमओआरडी)

भारत सरकार के सहयोग से

## सूची

### सत्र 1: जन योजना अभियान का परिचय

1. जन योजना अभियान की गतिविधियां
  - 1.1 ग्राम विकास के लिए योजना
  - 1.2 ग्राम सभा
  - 1.3 व्यापक सार्वजनिक सूचना
  - 1.4 योजना प्लस आवेदन पर जीपीडीपी का प्रकाशन।
  - 1.5 अभियान के लिए समर्पित पोर्टल
  - 1.6 जन योजना अभियान कार्य मर्दें
  - 1.7 जीपीडीपी के लिए ग्राम पंचायत सुविधा
  - 1.8 सुविधाकार की भूमिका

### सत्र 2: मिशन अंत्योदय डाटा संग्रह

- 2.1 मिशन अंत्योदय ढांचाकार्य
- 2.2 मिशन अंत्योदय कार्यान्वयन
- 2.3 'मिशन अंत्योदय' के तहत प्रमुख प्रक्रियाएं
- 2.4 मिशन अंत्योदय' के मुख्य परिणाम
- 2.5 मिशन अंत्योदय प्रारूप में डाटा संग्रह
- 2.6 ग्राम सभा द्वारा मान्यता

### सत्र 3: ग्राम सभा में फ्रंट लाइन श्रमिकों द्वारा प्रस्तुतिकरण

- 3.1 स्थानीय शासन और पंचायतें
- 3.2 ग्राम पंचायत
- 3.3 ग्राम पंचायतों के अनिवार्य कार्य
- 3.4 ग्राम पंचायतों के विकास या क्षेत्रीय कार्य
- 3.5 लाइन विभागों के सीमावर्ती श्रमिकों द्वारा प्रस्तुतिकरण
- 3.6 सात विशिष्ट योजनाओं के साथ संबद्ध बेहतर परिणामों की सुविधा

### सत्र 4: ग्राम पंचायत और ग्राम सभा की बैठकों की सुविधा

- 4.1 ग्राम पंचायत बैठक आयोजित करना
- 4.2 ग्राम पंचायत बैठक में चर्चा के लिए विषय
- 4.3 ग्राम पंचायत बैठकों के संचालन के लिए प्रक्रिया
- 4.4 ग्राम सभा
- 4.5 ग्राम सभा के सदस्य
  - 4.6 ग्राम सभा आयोजित करना
  - 4.7 ग्राम सभा में सरपंच की भूमिका
  - 4.9 ग्राम सभा की अनुसूची
  - 4.11 सभा की अधिसूचना
  - 4.12 ग्राम सभा के लिए कोरम
  - 4.13 जीपीडीपी के लिए विशेष ग्राम सभा का आयोजन
  - 4.14 सामुदायिक संगठन
  - 4.15 ग्राम सभा के लिए लोगों को मोबिलिज़ करना

#### 4.16 महिलाओं की भागीदारी

#### सत्र 5: जीपीडीपी की तैयारी के लिए समर्थन

- 5.1 आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजना
- 5.2 योजना क्या है
- 5.3 आर्थिक विकास क्या है
- 5.4 सामाजिक न्याय क्या है
- 5.5 भागीदारी योजना क्या है
- 5.6 जीपीडीपी क्या है और यह क्या करता है
- 5.7 स्थानीय योजना में उभरते मुद्दे और चुनौतियां:
- 5.8 कार्यकारी समूहों का गठन
- 5.9 पर्यावरण निर्माण / आईईसी गतिविधियां
- 5.10 डाटा संग्रह
- 5.11 स्थिति विश्लेषण
- 5.12 स्टेटस रिपोर्ट का विकास (डीएसआर)
- 5.13 विजनिंग अभ्यास
- 5.14 आवश्यकताओं की प्राथमिकता
- 5.15 संसाधन पहचान / आकलन
- 5.16 पंचायत विकास संगोष्ठी
- 5.17 योजना के संसाधनों का मिलान
- 5.18 लागत कम या कोई लागत / कम लागत विकास
- 5.19 पांचवीं अनुसूची क्षेत्रों में जीपीडीपी के लिए विशेष प्रक्रिया
- 5.20 ड्राफ्ट जीपीडीपी और इसकी स्वीकृति का प्रतिनिधित्व
- 5.21 योजना कार्यान्वयन
- 5.22 क्षमता निर्माण
- 5.23 जवाबदेही प्रणाली
- 5.24 दिशा पोर्टल

#### परिशिष्ट :

1. मॉडल सुविधाकार की रिपोर्ट
2. अनुसूची XI के 29 विषयों के संबंध में ग्राम पंचायत कार्यों की विस्तृत सूची
3. जन योजना अभियान (जीपीडीपी) के लिए विशेष ग्राम सभा के सुझावपरक एजेंडा मद
4. ग्राम पंचायत स्तर पर पर्यावरण निर्माण के लिए गतिविधियों की एक व्याख्यात्मक सूची
5. स्थिति विश्लेषण विकास विकल्प का एक उदाहरण उदाहरण
6. विकास स्थिति रिपोर्ट की संकेतक रूपलाईन (डीएसआर)
7. ग्राम पंचायत के आदेश पर निधियों के स्रोत
8. लागत कम या कोई लागत नहीं - कम लागत विकास

#### सत्र 1

### जन योजना अभियान का परिचय

# 'सब की योजना सब का विकास'

## सत्र उद्देश्य:

- लोगों की योजना अभियान क्या है
- ग्राम विकास के लिए योजना
- ग्राम सभा का आयोजन
- जीपीडीपी पर व्यापक सार्वजनिक सूचना
- सुविदा प्रदाता की भूमिका

## सत्र संक्षिप्त:

- प्रभावी ग्रामसभा में 31 लाख निर्वाचित पंचायत नेताओं और डीएआर तहत के एनआरएलएम-5.25 करोड़ एसएचजी महिलाओं की भूमिका को सुदृढ़ करना।
- 2018-19 में किए गए प्रगति के साक्ष्य आधारित आकलन और ग्यारहवीं XI अनुसूची के सभी 29 विषयों में 2019-20 के प्रस्ताव।
- लोक सूचना अभियान सभी कार्यक्रमों की योजनाओं, वित्त, आदि पर ग्राम डिस्प्ले बोर्ड पर पूर्ण सार्वजनिक प्रकटीकरण
- संरचित ग्राम सभा की बैठकें 2 अक्टूबर -31 दिसंबर, 2018 में फैली हुई, जिसमें ग्यारहवीं अनुसूची में सभी 29 क्षेत्रों के सीमावर्ती श्रमिक पर्यवेक्षकों द्वारा उपस्थिति और / प्रस्तुति शामिल है।
- प्लानप्लस को व्यावहारिक और समग्र ग्राम पंचायत विकास योजना के लिए मजबूती प्रदान करना

## सत्र विषय:

आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) की तैयारी के लिए ग्राम पंचायतों को अनिवार्य किया गया है। जीपीडीपी योजना की प्रक्रिया को व्यापक और सहभागिता प्रक्रिया के आधार पर होना चाहिए जो संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 विषयों से संबंधित सभी संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों / लाईन विभागों की योजनाओं के साथ पूर्ण अभिसरण है। ग्रामीण भारत के परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर प्रमुख योजनाओं के प्रभावी और कुशल कार्यान्वयन में पंचायतों की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई है। जन योजना अभियान को 2 अक्टूबर से 31 दिसंबर, 2018 तक 'सबकी योजना सबका विकास' के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। अभियान के दौरान, अगले वित्तीय वर्ष अर्थात् के लिए 2019-20 ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) तैयार करने के लिए संरचित ग्राम सभा की बैठक आयोजित की जाएगी।

जीपीडीपी अभियान पंचायती राज संस्थानों (पीआरआड.) और राज्य के संबंधित लाइन विभागों के बीच अभिसरण के माध्यम से ग्रामसभा स्तर पर योजना बनाने के लिए एक गहन और संरचित अभ्यास होगा। इस अभियान के हिस्से के रूप में, सभी ग्राम पंचायतों के संबंध में मिशन अंत्योदय (एमक) डाटा संग्रह का अभ्यास पूरा करने का भी प्रस्ताव है। यह आंकड़ा वर्तमान में लगभग 44,108 ग्राम पंचायत के लिए उपलब्ध है और लगभग 2.49 लाख ग्राम पंचायत में से ग्राम पंचायत की शेष राशि के लिए एकत्रित किया जाना आवश्यक है।

**1. जन योजना अभियान की गतिविधियां:** जन योजना अभियान के दौरान उठाए जाने वाली मुख्य गतिविधियां निम्नलिखित हैं।

**1.1 ग्राम विकास के लिए योजना :** अभियान अवधि के दौरान ग्राम पंचायत विकास योजना के हिस्से के रूप में ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध सभी 29 विषयों की योजना आवश्यक है। इस अभियान के प्रमुख मूवर्स ग्राम पंचायत ही होंगे। एसएचजी, लाइन विभागों के गांव के फ्रंट लाइन श्रमिक, और पंचायत सचिव, ग्राम रोजगार, सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों, एएनएम, आशा और आईसीडीएस कर्मचारियों के ग्राम पंचायत स्तर के अधिकारियों को जीपीडीपी योजना प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल होने की आवश्यकता है।

**1.2 ग्राम सभा:** 2 अक्टूबर - 31 दिसंबर, 2014 को फैले देश के लगभग 2.49 लाख पीआरआई / स्थानीय ग्रामीण निकायों में से प्रत्येक में संरचित ग्राम सभा आयोजित की जानी चाहिए, जिसमें संबंधित विभागों / पर्यवेक्षकों द्वारा भौतिक उपस्थिति और प्रस्तुतियां शामिल हैं ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 विषयों। राज्य ग्राम सभा में मौजूद सीमावर्ती श्रमिकों / पर्यवेक्षकों की भागीदारी सुनिश्चित करेंगे जो विभाग की उपलब्ध योजनाओं, चालू वर्ष में चल रही गतिविधियों और ग्रामसभा में वित्त वर्ष 2019-20 के लिए प्रस्तावित गतिविधियों के बारे में विस्तृत प्रस्तुति देंगे।

ग्राम सभा में ग्रामीणों की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ग्राम पंचायत को गहन आईसीडीपी का उपयोग करना है। सरपंच को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पीआरआई के निर्वाचित प्रतिनिधियों की सभी समितियों की बैठकें इस अवधि के दौरान भी आयोजित की जाएंगी। इस अभियान अवधि के दौरान योजना समिति को एसएचजी महिलाओं को शामिल करने और 29 विषयों के क्षेत्रों में विभिन्न गतिविधियों के संचालन में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। ग्राम संगठनों (वीओ) को जीपीडीपी में एकीकरण के लिए विशेष ग्रामसभा में गरीबी में कमी की योजना पेश करनी चाहिए।

**1.4 सरकारी विभागों की सभी योजनाओं पर पूर्ण प्रकटीकरण के लिए व्यापक सार्वजनिक सूचना अभियान,** लाभार्थियों की सूची प्रदर्शित करना, ग्राम पंचायत कार्यालय में लोक सूचना बोर्ड और ऑनलाइन सेल फोन आधारित ऐप (ग्राम संवाद ऐप) के माध्यम से ऑनलाइन। सभी योजनाओं के बारे में व्यापक और पूर्ण सार्वजनिक जानकारी ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) की बेहतर तैयारी की सुविधा प्रदान करेगी क्योंकि सभी संसाधन पूरी तरह से मैप किए जाएंगे, और आम तौर पर जन जागरूकता पैदा करने में मदद मिलेगी। सार्वजनिक प्रकटीकरण के लिए योजनाओं के तहत हस्तक्षेप की शारीरिक और वित्तीय प्रगति के साथ ग्राम पंचायत की पृष्ठभूमि जानकारी के साथ एक प्रमुख स्थान पर प्रत्येक ग्राम पंचायत में 20 फीट x 10 फीट के आकार का एक सार्वजनिक सूचना बोर्ड स्थापित किया जाना चाहिए। आकृति 1 में सार्वजनिक सूचना बोर्ड का एक चित्रकारी डिज़ाइन दिया गया है

**1.5 प्लानप्लस आवेदन पर जीपीडीपी का प्रकाशन:** विशेष ग्रामसभा में चर्चा के बाद और ग्रामसभा की मंजूरी के साथ जीपीडीपी के गठन के बाद, अंतिम योजना पीडीएफ प्रारूप में प्लानप्लस आवेदन में प्रकाशित की जानी चाहिए। सार्वजनिक प्रकटीकरण के लिए योजना की हार्ड कॉपी ग्राम पंचायत के कार्यालय में रखी जा सकती है। इसके अलावा, कार्यान्वयन की शुरुआत में सार्वजनिक सूचना बोर्ड पर जीपीडीपी की संपत्ति निर्माण गतिविधियां प्रकाशित की जा सकती हैं।

**1.6 अभियान के लिए समर्पित पोर्टल:** अभियान पर वास्तविक समय सूचना साझा करने की निगरानी और सुविधा के लिए, एमओपीआर एक पोर्टल ([www.gpdp.nic.in](http://www.gpdp.nic.in)) विकसित कर रहा है। पोर्टल को कार्यान्वित किया जाएगा। अभियान से पहले, उसके दौरान और बाद में विभिन्न गतिविधियों पर मूल्यांकन करने के लिए, राज्यों को पोर्टल पर विभिन्न रिपोर्टिंग प्रारूपों में जानकारी प्रदान करने की आवश्यकता है। पोर्टल के लिए उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड कैस्केडिंग मोड में उत्पन्न किया जाएगा। राज्य नोडल अधिकारी के लिए उपयोगकर्ता स्तर और पासवर्ड केंद्रीय स्तर पर जिला, ब्लॉक और सुविधा स्तर के लिए उत्पन्न किया जाएगा, यह उनके अगले ऊपरी स्तर पर उत्पन्न होगा। लाइन विभागों के राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी नामित दिनों पर ग्राम सभा (जीएस) की बैठकों के लिए नियुक्त किए जाने वाले सीमावर्ती श्रमिकों के नाम नियुक्त और अपलोड करने के लिए जिम्मेदार होंगे।

**1.7 लोगों की योजना अभियान कार्य मदें:** निम्नलिखित लोगों के योजना अभियान के लिए कार्य बिंदु निम्नलिखित हैं

1. अभियान के लिए नोडल अधिकारी की नियुक्ति, ग्राम पंचायत (मिशन अंत्योदय) के आधारभूत सर्वेक्षण और वेब पोर्टल पर पंजीकरण (www.gpdp.nic.in)
2. हर ग्राम पंचायत के लिए सुविधा के लिए नियुक्ति
3. ग्राम सभा के आयोजन के लिए ग्राम सभावार कैलेंडर का अंतिम रूप
4. नामित दिनों पर ग्राम सभा की बैठकों में संरचित प्रस्तुति के लिए 29 विषयों से संबंधित सभी विभागों के सीमावर्ती श्रमिकों को नियुक्त करना
5. जीपीडीपी के लिए विशेष ग्राम सभा आयोजित करना  
प्रत्येक ग्राम पंचायत में सार्वजनिक सूचना बोर्ड का प्रदर्शन और वेब पोर्टल पर इसके भू-टैग किए गए तस्वीरें ग्राफ अपलोड करना
6. प्रगति पर ग्रामसभा की बैठकों की भू-टैग की गई तस्वीरों को अपलोड करना
7. जीपीडीपी की तैयारी

**1.8 जीपीडीपी के लिए ग्राम पंचायत सुविधा:** ग्राम पंचायत प्रति एक सुविधा होगी जो सरपंच की देखरेख और मार्गदर्शन के तहत जीपीडीपी तैयार करने में ग्राम पंचायत का समर्थन करेगा। नियोजन अभ्यास करने के लिए, निर्वाचित प्रतिनिधियों, पंचायत सचिव, ग्राम रोजगार सेवा, स्कूल शिक्षक, आशा एडब्ल्यूडब्ल्यू, एएनएम, फिलैन्थ्रोपिक और स्वैच्छिक मानव संसाधनों के साथ सुविधाकर्ता समग्र और दूरदर्शी योजना के साथ आने में ग्राम पंचायत की सहायता करते हैं। राज्य सरकार / जिला प्रशासन द्वारा सभी लाइन विभागों को जारी किए गए निर्देशों को इन सदस्यों की पूरी तरह से दिल की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए लीवरेज किया जाना चाहिए। जीपीडीपी तैयार करने के सभी कार्यों की पूर्ति में सहायक और उनकी टीम ग्राम पंचायत का सीमावर्ती कार्यात्मक समूह होगा।

**1.9 सुविधाकारिता का भूमिका :** निम्नलिखित लोगों के योजना अभियान के लिए सुविधाकर्ता की भूमिका और जिम्मेदारियां निम्नलिखित हैं

1. एमए मोबाइल ऐप का उपयोग कर मिशन अंत्योदय (एमक) के तहत सर्वेक्षण करें।
2. भाग लेने वाले मंत्रालयों / विभागों के सीमावर्ती कर्मचारियों के साथ समन्वय
3. नामित दिन पर जीपीडीपी के लिए विशेष ग्राम सभा की सुविधा
4. ग्रामसभा के दौरान अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / महिला / विकलांग जैसे कमजोर वर्गों सहित सामुदायिक संगठन सुनिश्चित करें
5. पोर्टल पर ग्राम सभा के आचरण के संबंध में एक रिपोर्ट जमा करें
6. जीपीडीपी की तैयारी की सहायता
7. प्लानप्लस पर जीपीडीपी अपलोड करें

चित्रा 1: लोक सूचना बोर्ड का चित्रकारी डिजाइन

#	क्षेत्र	निवेश
1.	ग्राम सभा में उपस्थित लोगों की संख्या	< गणना >
2.	ग्राम सभा में उपस्थित अनुसूचित जासतियों की संख्या	< गणना >
3.	ग्राम सभा में उपस्थित अनुसूचित जनजासतियों की संख्या	< गणना >
4.	ग्राम सभा में उपस्थित स्व सहायता समूह सदस्यों की संख्या	< गणना >
5.	ग्राम सभा में उपस्थित महिलाओं की संख्या	< गणना >
6.	फ्रंटलाईन कार्यकर्ता उपस्थित एवं किया गया प्रस्तुतीकरण	
6.1	पंचायती राज विभाग	< जांच बॉक्स >
6.2	ग्रामीण विकास विभाग	< जांच बॉक्स >
6.3	कृषि विभाग	< जांच बॉक्स >
6.4	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	< जांच बॉक्स >
6.5	महिला एवं बाल विकास विभाग	< जांच बॉक्स >
6.6	ऊर्जा विभाग	< जांच बॉक्स >
6.7	रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग	< जांच बॉक्स >
6.8	पशुपालन एवं दुग्ध निर्माण विभाग	< जांच बॉक्स >
6.9	राजस्वा विभाग	< जांच बॉक्स >
6.10	पेयजल विभाग	< जांच बॉक्स >
6.11	नई एवं नवीनीकरण ऊर्जा विभाग	< जांच बॉक्स >
6.12	शिक्षा विभाग	< जांच बॉक्स >
6.13	कौशल विकास विभाग	< जांच बॉक्स >
6.14	सामाजिक न्याय विभाग	< जांच बॉक्स >
6.15	खाद्य एवं आपूर्ति विभाग	< जांच बॉक्स >
6.16	वित्त विभाग	< जांच बॉक्स >
6.17	सिंचाई विभाग	< जांच बॉक्स >
6.18	मछली पालन विभाग	< जांच बॉक्स >
6.19	वन विभाग	< जांच बॉक्स >
6.20	लघु उद्योग विभाग	< जांच बॉक्स >
6.21	औद्योगिक विभाग	< जांच बॉक्स >
6.22	खादी / ग्राम उद्योग विभाग	< जांच बॉक्स >
6.23	< राज्य > बिजली बोर्ड	< जांच बॉक्स >
6.24	ग्रामीण सड़क विकास विभाग	< जांच बॉक्स >
6.25	< राज्य > लोक निर्माण विभाग	< जांच बॉक्स >
7.	मिशन अन्त्योदय डाटा की वैधता एवं प्रस्तुतीकरण	< जांच बॉक्स >
8.	निर्धनता संबंधी मुद्दे एवं निर्धनता घटाव योजनाओं के संबंध में स्व-सहायता समूहों द्वारा प्रस्तुतीकरण	< जांच बॉक्स >
9.	जीपीडीपी पर चर्चा	< जांच बॉक्स >
9.1	वर्ष 2019-2020 के दौरान ग्राम पंचायतों के लिए उपलब्ध किए जाने वाले संसाधनों पर चर्चा	< जांच बॉक्स >
9.2	चालू वर्ष क्रियाकलाप एवं उपयोग में लाई गई निधियों की प्रगति की समीक्षा	< जांच बॉक्स >
9.3	मिशन अन्त्योदय सर्वेक्षण एवं प्रस्तावित हस्तक्षेपों से शिनाख्त किए गए अंतरालों पर परिचर्चा	< जांच बॉक्स >
9.4	ग्राम सभा द्वारा पारित अंतिम जीपीडीपी क्रियाकलापों पर संकल्प	< जांच बॉक्स >
10.	ग्राम सभा के भू-संलग्न छायाचित्र	अपलोड
11.	लोक सूचना बोर्ड का भू-संलग्न छायाचित्र	अपलोड

12.	ग्राम सभा का वीडियो प्रगति पर (वैकल्पिक)	अपलोड
-----	--	-------

## सत्र 2:

# मिशन अंत्योदय डाटा का संग्रह

### सत्र उद्देश्य:

1. मिशन अंत्योदय के ढांचे का मूल्यांकन
2. 'मिशन अंत्योदय' के तहत प्रक्रियाएं
3. 'मिशन अंत्योदय' के माध्यम से अनुमानित परिणाम
4. ग्राम पंचायत में डाटा संग्रह

### सत्र संक्षिप्त:

- ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के तहत सामाजिक क्षेत्र व्यय, व्यय का एक बड़ा हिस्सा है। लेकिन गरीबी की बहुआयामीता के कारण, अंतर है। आवश्यकता की करने अनुकूलित को निवेश से माध्यम के दृष्टिकोण क्षेत्रीय-
- संविधान में 73 वें संशोधन के बाद, पीआरआई जमीनी स्तर पर विकास के प्रयासों का तेजी से नेतृत्व कर रहे हैं। हालांकि, वंचितताओं से निपटने के लिए योजना, प्रशासन और संसाधन आवंटन की कई परतों के कारण, समय और स्थान में अक्सर प्रयास किए जाते हैं, जिससे उप-परिणाम प्राप्त होते हैं। इस प्रकार, ग्राम पंचायत के साथ अपनी मूल इकाई के रूप में अभिसरण योजना।
- ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी) ने 2011 में सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना आयोजित की। एसईसीसी डाटा बहुआयामी वंचितों के परिप्रेक्ष्य से घर की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों को समझने की अनुमति देता है (उदाहरण के लिए भूमिहीनता, एकल महिला, एससी / एसटी की अध्यक्षता में परिवार घर आदि)।
- मिशन अंत्योदय 'यह सुनिश्चित करने के लिए अभिसरण, उत्तरदायित्व और मापनीय परिणामों पर आधारित है कि संसाधनों को प्रभावी रूप से एसईसीसी के प्रत्येक वंचित घर के लिए स्थायी आजीविका प्रदान करने में प्रबंधित किया जाता है।

### सत्र विषय

**2.1 मिशन अंत्योदय ढांचा कार्य :** मिशन अंत्योदय जीवन और आजीविका को बदलने वाले मानकों पर मापनीय प्रभावी परिणामों के लिए एक अभिसरण ढांचा है। भारत में, 2011 के सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना (एसईसीसी) के अनुसार 8.88 करोड़ परिवार वंचित और गरीब परिवारों को बहु-आयामी वंचितों के परिप्रेक्ष्य से लेकर आश्रयहीनता, भूमिहीनता, एकल महिलाओं की अध्यक्षता वाले परिवार, एससी / एसटी परिवार या परिवार में अक्षम सदस्य इन घरों को मजदूरी निर्माण, कौशल निर्माण, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और आजीविका निर्माण जैसे क्षेत्रों में सरकार की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के तहत लक्षित हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है। 'मिशन अंत्योदय' ग्राम पंचायतों के साथ सरकारी हस्तक्षेपों को संसाधनों को पूल करके संतुष्टि दृष्टिकोण का पालन करके नियोजन के लिए मूल इकाई के रूप में अभिसरण करना चाहता है - मानव और वित्तीय - स्थायी आजीविका सुनिश्चित करने के लिए।

**2.2 कार्यान्वयन:** एक ग्राम पंचायत परिवर्तन की निगरानी और उद्देश्य मानदंडों के आधार पर रैंकिंग के लिए मूल इकाई है। ग्राम पंचायतों के विविध आकार को देखते हुए, राज्यों द्वारा लगभग 50,000 ग्राम पंचायतों के 5,000 क्लस्टर चुने गए हैं। मिशन अंत्योदय ग्रामीण आजीविका के परिवर्तन को और तेज करने के लिए पेशेवरों, संस्थानों और उद्यमों के नेटवर्क के साथ साझेदारी को प्रोत्साहित करता है। स्व-सहायता समूह (एसएचजी) अपनी सामाजिक पूंजी और सामाजिक संगठनात्मकता के लिए उनकी सिद्ध क्षमता के कारण अभिसरण दृष्टिकोण के लिए समर्थक हैं। जोर न

केवल भौतिक आधारभूत संरचना पर बल्कि कृषि, बागवानी, पशुपालन गतिविधियों को मजबूत बनाने के साथ-साथ मिशन अंत्योदय क्लस्टर में एसएचजी विस्तार को दी गई प्राथमिक प्राथमिकता के साथ सामाजिक आधारभूत संरचना पर भी है।

### 2.3 'मिशन अंत्योदय' के तहत प्रमुख प्रक्रियाएं:

1. परिवारों के आधारभूत सर्वेक्षण करें और समय-समय पर प्रगति की निगरानी करें।
2. ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए लक्षित कार्यक्रमों का अभिसरण सुनिश्चित करें।
3. पीआरआई, सामुदायिक संगठनों, गैर सरकारी संगठनों, एसएचजी संस्थानों और विभिन्न विभागों के क्षेत्र-स्तर के कार्यकर्ताओं (जैसे आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी श्रमिक, एएनएम इत्यादि) के बीच ग्राम पंचायत / क्लस्टर में साझेदारी को संस्थागत बनाना।
4. संस्थानों और पेशेवरों के साथ साझेदारी के माध्यम से उद्यम को बढ़ावा देना।

### 2.4 'मिशन अंत्योदय' के मुख्य परिणाम:

1. जीपीडीपी / क्लस्टर विकास योजनाओं के अनुरूप योजनाओं के प्राथमिक कार्यान्वयन के माध्यम से चयनित ग्राम पंचायत क्लस्टर के लिए मजबूत आधारभूत आधार।
2. ग्राम पंचायत / क्लस्टर में हितधारकों की विस्तृत श्रृंखला को शामिल करने वाली योजनाओं की भागीदारी योजना और कार्यान्वयन को बढ़ावा देने वाली प्रभावी सामाजिक पूंजी।
3. गैर कृषि क्षेत्र, ग्रामीण युवाओं और महिलाओं की स्किलिंग, मूल्य श्रृंखलाओं के विकास और उद्यम के प्रचार सहित विविध आजीविका के माध्यम से उन्नत आर्थिक अवसर।
4. पीआरआई, सार्वजनिक प्रकटीकरण, ग्राम पंचायत स्तर औपचारिक और सामाजिक लेखा परीक्षा जैसे सामाजिक उत्तरदायित्व उपायों की क्षमता निर्माण हालांकि लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को सुदृढ़ किया गया।

**2.5 मिशन अंत्योदय प्रारूप में डाटा संग्रह:** मिशन अंत्योदय अभिसरण, उत्तरदायित्व और मापनीय परिणामों पर आधारित है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एसईसीसी, 2011 के आधार पर हर वंचित परिवार के लिए संसाधनों को स्थायी रूप से आजीविका प्रदान करने में संसाधन प्रभावी ढंग से प्रबंधित किए जाते हैं। फ्रेमवर्क तकनीक का उपयोग यह सुनिश्चित करने के लिए करता है कि लाभ उन लोगों तक पहुंचें जो एसईसीसी डाटा के अनुसार सबसे योग्य हैं। बेसलाइन के खिलाफ प्रगति को मापने के लिए संकेतकों के परिभाषित सेट के खिलाफ अंत तक लक्ष्यीकरण सुनिश्चित करने के लिए एक सामान्य स्थानीय प्रशासन निर्देशिका (एलजीडी) कोड का उपयोग करके एक मजबूत प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) योजनाओं के डाटा बेस से जुड़ा हुआ है। डाटा कई विभागों को एकत्रित किया जाना है। केंद्र और राज्य सरकारों के 25 से अधिक विभाग और 18 मंत्रालय इस मिशन में अपने विशिष्ट कार्यक्रमों और योजनाओं के माध्यम से भाग ले रहे हैं। पूर्ण पारदर्शिता के लिए विभिन्न योजनाओं के डाटा को सार्वजनिक क्षेत्र में रखना होगा। डाटा संग्रह के लिए मिशन अंत्योदय प्रारूप परिशिष्ट में दिया गया है। मिशन अंत्योदय मोबाइल एप्लिकेशन का उपयोग करके डाटा एकत्र किया जाना है।

**2.6 ग्रामसभा द्वारा मान्यता:** टीम को प्रत्येक गांव में एकत्र की गई जानकारी की एक प्रिंट प्रति डाउनलोड करने की आवश्यकता होगी और इसे अनुमोदन के लिए ग्राम सभा के समक्ष रखा जाएगा। प्रतिक्रिया के आधार पर, आवश्यक परिवर्तन शामिल किए जा सकते हैं।

### सत्र 3:

## ग्रामसभा में सीमावर्ती श्रमिकों द्वारा प्रस्तुतिकरण

### सत्र उद्देश्य:

- स्थानीय शासन और पंचायत
- पंचायतों के अनिवार्य कार्य
- पंचायतों के विकास / क्षेत्रीय कार्य
- लाईन विभागों के सीमावर्ती श्रमिकों द्वारा प्रस्तुतिकरण
- 7 विशिष्ट योजनाओं के साथ संबद्ध बेहतर परिणामों की सुविधा

### सत्र संक्षिप्त:

- पंचायती राज का विचार स्थानीय स्तर पर सामुदायिक भागीदारी और सामूहिक निर्णय लेने अर्थात् आत्म पर स्तर जमीनी उद्देश्य पीछे के स्थापना की व्यवस्था राज पंचायती है। आधारित पर शासन-लोगों को शक्तियों का प्रतिनिधित्व करके, गांव स्तर पर लोकतंत्र स्थापित करना था।
- अनुच्छेद 243 जी आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय से संबंधित मामलों पर काम करने के लिए पंचायती राज संस्थानों (पीआरआड.) को शक्ति प्रदान करता है। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, पंचायतों को 11 वीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 विषयों को सौंपा गया है।

**3.1 स्थानीय शासन और पंचायत:** संविधान के 73 वें संशोधन ने ग्रामीण स्थानीय शासन परिदृश्य में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। संविधान के अनुच्छेद 243 जी, ग्यारहवीं अनुसूची के साथ पढ़ते हैं, यह निर्धारित करता है कि संबंधित राज्य सरकार को पंचायतों को ऐसी शक्तियों और अधिकार को समर्पित करने की आवश्यकता है। प्रत्येक संस्थान का अधिकार क्षेत्र एक विशिष्ट क्षेत्र तक ही सीमित है। व्यापक संवैधानिक ढांचे के भीतर, राज्यों ने कानूनों और तैयार नियमों को लागू किया है जो उनकी संरचना और कार्यों को परिभाषित करते हैं। पंचायती राज का विचार स्थानीय स्तर पर सामुदायिक भागीदारी और सामूहिक निर्णय लेने पर आधारित है। संविधान के तहत पीआरआई की मूल संरचना भारत के राज्यों में समान है। प्रत्येक राज्य में पीआरआई की अपनी विशेषताओं और कार्यात्मक जिम्मेदारियां होती हैं।

**3.2 ग्राम पंचायत:** ग्राम पंचायत संविधान के तहत पहली औपचारिक लोकतांत्रिक संस्था है। जनसंख्या के आकार के आधार पर ग्राम पंचायत को संबंधित राज्य कानून के तहत एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र के साथ परिभाषित किया गया है, जिसमें एक गांव या संगत गांवों का समूह शामिल हो सकता है। ग्राम पंचायत प्रत्येक गांव के साथ आवश्यक रूप से सह टर्मिनस नहीं हैं। ग्राम पंचायत मतदाताओं की संख्या के आधार पर ग्राम पंचायत को निर्वाचन क्षेत्रों या वार्डों में बांटा गया है। इनमें से प्रत्येक वार्ड से, एक सदस्य चुने जाते हैं। इन निर्वाचित सदस्यों के निकाय को ग्राम पंचायत कहा जाता है। पीआरआई के कार्यों को व्यापक रूप से अनिवार्य कार्यों और विकास, या क्षेत्रीय कार्यों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।

**3.3 ग्राम पंचायतों के अनिवार्य कार्य:** नागरिक सुविधाओं के संचालन और रखरखाव के लिए प्रावधान पारंपरिक रूप से स्थानीय सरकारों के प्रमुख कार्यों रहे हैं। अनिवार्य कार्य वे मूल या बुनियादी कार्य हैं जिन्हें ग्राम पंचायतों को अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निर्वहन करने की आवश्यकता होती है। अनिवार्य कार्य ज्यादातर नागरिक और नियामक कार्य होते हैं। इन कार्यों को करने के लिए कोई अन्य एजेंसी नहीं है। निम्नलिखित ग्राम पंचायत के अनिवार्य कार्य हैं।

1. आर्थिक विकास, सेवा वितरण और सामाजिक न्याय के लिए कार्यक्रमों की योजना और कार्यान्वयन।
2. ग्राम सड़क, भवन, बाजार, सार्वजनिक पार्क और खेल मैदान आदि का निर्माण और रखरखाव

3. सार्वजनिक सड़कों और अन्य स्थानों के प्रकाश की व्यवस्था और रखरखाव प्रदान करना।
4. सार्वजनिक सड़क और अन्य सार्वजनिक स्थानों की सफाई सहित कुल स्वच्छता का रखरखाव।
5. जलन और शमशान मैदानों का रखरखाव और विनियमन।
6. मांस, मछली और अन्य विनाशकारी खाद्य वस्तुओं की बिक्री का विनियमन।
7. खाने और मनोरंजन प्रतिष्ठानों का लाइसेंस, और आक्रामक और खतरनाक व्यापारों के विनियमन सहित खाद्य विसर्जन की रोकथाम।
8. ग्राम सभा के माध्यम से विभिन्न कार्यक्रमों के तहत लाभार्थियों का चयन
9. जन्म, मृत्यु और विवाह का पंजीकरण।
10. ग्राम पंचायतों के वार्षिक बजट की तैयारी।
11. सार्वजनिक संपत्तियों पर अतिक्रमण को हटाने।

**3.4 ग्राम पंचायतों के विकास या क्षेत्रीय कार्य:** ग्रामीण समुदाय की विविध सामाजिक आर्थिक जरूरतों को संबोधित करने में लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित स्थानीय सरकारों के रूप में पीआरआई की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। ग्राम पंचायत की परामर्श अनुमोदन में विभिन्न लाइन विभागों द्वारा संचालित कार्यों को क्षेत्रीय कार्यों के रूप में जाना जाता है। ग्राम पंचायतों के क्षेत्रीय कार्यों में संविधान के अनुसूची XI में उल्लिखित गतिविधियों का समावेश होता है, जिसमें 29 विषयों के संबंध में कार्यों की एक सूचक सूची है, जिसे ग्राम पंचायत का निर्वहन परिशिष्ट I में दिया जा सकता है।

**3.5 लाइन विभागों के सीमावर्ती श्रमिकों द्वारा प्रस्तुतिकरण:** अनुसूचित जनजाति में सूचीबद्ध 29 विषयों से संबंधित लाइन विभागों के सीमावर्ती श्रमिक लोगों के योजना अभियान के दौरान ग्राम सभा में भाग लेंगे और बजट आवंटन, कार्यों सहित उनके द्वारा लागू की जा रही योजनाओं से संबंधित संरचित प्रस्तुति तैयार करेंगे। संविधान के अनुच्छेद 243 जी के अनुसार पंचायतों को दी गई शक्तियों और कार्यों सहित योजनाओं के तहत किसी भी योजना के तहत प्रगति और योग्यता मानदंडों में। लाइन विभागों से सीमावर्ती श्रमिकों द्वारा किए जाने वाले मॉडल प्रस्तुति परिशिष्ट II में दी गई है।

परिशिष्ट I

अनुसूची XI के 29 विषयों के संबंध में ग्राम पंचायत कार्यों का चित्रण की व्याख्यात्मक सूची

क्र.सं	विषय	कार्यात्मक जिम्मेदारियों की व्याख्यात्मक सूची
1	कृषि विस्तार सहित कृषि	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. फसलों और फसल पैटर्न के डाटा बेस बनाए रखें</li> <li>2. विभिन्न इनपुट जैसे बीजों, उर्वरकों, कीटनाशकों आदि की जरूरतों का आकलन करें।</li> <li>3. किसानों को किराए पर देने के लिए संयंत्र संरक्षण और कृषि कार्यान्वयन की खरीद करें</li> <li>4. कृषि स्वयं सहायता समूहों के गठन में सहायता करें</li> <li>5. किसानों की क्रेडिट जरूरतों का आकलन करें</li> <li>6. ऋण की वसूली के लिए क्रेडिट संस्थानों की सहायता करें।</li> <li>7. गांव खेतों में विस्तार कर्मचारियों की यात्रा की निगरानी करें</li> <li>8. परीक्षणों और प्रदर्शनों के संचालन के लिए उपयुक्त भूखंडों की पहचान करें</li> <li>9. किसानमेलों में भाग लेने के लिए किसानों का चयन करें</li> <li>10. कार्बनिक उर्वरकों और वर्मिकल्चर के उपयोग में जागरूकता उत्पन्न करें</li> <li>11. सरकार द्वारा स्वीकृत किसानों को सब्सिडी और अन्य सहायता वितरित करें</li> <li>12. कृषि संबंधी मुद्दों पर कृषि विभाग को फीडबैक प्रदान करें।</li> <li>13. नर्सरी बागवानी और सब्जी की खेती के विकास को प्रोत्साहित करें। चरागाह भूमि का विकास।</li> </ol>

2	भूमि सुधार और मृदा संरक्षण	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. लाइन विभाग की सहायता करें। मिट्टी परीक्षण मिट्टी संरक्षण कार्य के लिए अधिकारी।</li> <li>2. मिट्टी संरक्षण कार्य को बनाए रखने के लिए संरक्षण, संरक्षण निगरानी।</li> <li>3. अपनी संपत्तियों, ग्रेडिंग इत्यादि के साथ मिलकर मिट्टी के उपयोग के लिए जागरूकता पैदा करें।</li> <li>4. भूमि का इष्टतम और टिकाऊ उपयोग।</li> <li>5. इसे खेती करने के लिए अपशिष्ट भूमि और सीमांत भूमि के पुनर्जनन को बढ़ावा देना</li> </ol>
3	लघु सिंचाई	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ग्राम पंचायत के भीतर सभी मामूली सिंचाई परियोजनाओं को बनाए रखें</li> <li>2. परियोजना के निष्पादन में उनकी प्रत्यक्ष भागीदारी के लिए वाटरशेड समितियों का गठन</li> <li>3. ग्रामसभा के माध्यम से वाटरशेड विकास के लिए भूमि / जल उपयोग योजना को मंजूरी दें</li> <li>4. लाभार्थियों का चयन करें और वाटरशेड के तहत व्यक्तिगत कार्यों को निष्पादित करने के लिए उन्हें सहायता प्रदान करें</li> <li>5. वाटरशेड परियोजना के तहत बनाई गई सामुदायिक संपत्तियों को रखरखाव रखें</li> </ol>
4	पशुपालन,	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. विभिन्न कार्यक्रमों के तहत लाभार्थियों की पहचान करें।</li> <li>2. लोगों को गुणवत्ता नस्लों को बनाए रखने और पशुओं को बनाए रखने की आधुनिक तकनीकों को अपनाने के लिए प्रेरित करें।</li> <li>3. महामारी के बाहर तोड़ने की रिपोर्ट करें</li> <li>4. दूध उत्पादक सहकारी समितियों का आयोजन करने में सहायता करें।</li> <li>5. डेयरी विकास कार्यक्रम के लिए लाभार्थियों की पहचान करें</li> <li>6. ग्रामीण लाइव स्टॉक इकाइयों के कामकाज का पर्यवेक्षण करें</li> <li>7. मिनी पोल्ट्री खेतों को प्रोत्साहित करें</li> </ol>

5	मछली पालन	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. मत्स्यपालन के लिए गांव तालाब विकसित करें।</li> <li>2. विभिन्न कार्यक्रमों के तहत सहायता के लिए लाभार्थियों की पहचान करें।</li> <li>3. नौकाओं, जाल और अन्य उपकरणों के वितरण में सहायता ब्लॉक पंचायत।</li> <li>4. फिशपाँड और टैंक सुधार निष्पादित करें।</li> <li>5. मछली पकड़ने के अधिकारों के लिए गांव तालाब लीजपर ले ।</li> <li>6. मछुआरों को बीमा योजनाएं लेने के लिए प्रोत्साहित करें</li> <li>7. आपदाओं से प्रभावित मछुआरों के परिवारों की हानि, क्षति और राहत आवश्यकताओं का आकलन करें</li> </ol>
6.	सामाजिक वानिकी	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. रिजर्व वन क्षेत्रों को छोड़कर, सभी खाली सरकारी भूमि के रोपण / जंगल के लिए उपयुक्त स्थानों पर सूची आयोजित करें।</li> <li>2. मांग सर्वेक्षण के आधार पर उपयुक्त नर्सरी एक्शन प्लान की तैयारी।</li> <li>3. सभी रिक्त भूमि पर वनों के लिए उपयुक्त वार्षिक कार्य योजनाओं की तैयारी।</li> <li>4. विकेन्द्रीकृत लोगों की नर्सरी को बढ़ावा देना और विस्तार करना ।</li> <li>5. स्थानीय समुदायों की जरूरतों को पूरा करने के लिए सभी खाली सरकारी भूमि पर ईंधन, चारा और छोटे लकड़ी के बागानों को बढ़ाएं।</li> </ol>
7.	लघु वन उत्पाद (एमएफपी)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. एमएफपी प्रजातियों को लगाने के इच्छुक परिवारों की पहचान में सहायता करें।</li> <li>2. वृक्षारोपण के लिए एमएफपी रोपण वितरित करें।</li> <li>3. बिक्री से पहले एमएफपी को संग्रह और प्राथमिक प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन को बढ़ावा देना।</li> <li>4. एमएफपी कलेक्टरों को समय पर भुगतान और पर्याप्त संग्रह शुल्क सुनिश्चित करें।</li> </ol>
8.	लघु उद्योग	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. पारंपरिक और लघु उद्योगों को बढ़ावा देना ।</li> </ol>
9	खादी, गांव और कुटीर उद्योग	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. खादी और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना ।</li> <li>2. हस्तशिल्प को बढ़ावा देना ।</li> </ol>

10	ग्रामीण आवास	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. बेघर के लिए भूमि और घर की पहचान और प्रावधान ।</li> <li>2. ग्रामीण आवास कार्यक्रमों के लिए लाभार्थियों की पहचान।</li> </ol>
11	पेयजल प्रणाली	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ग्राम सभा की भागीदारी के माध्यम से योजनाओं और स्थानों की पहचान करें</li> <li>2. अपने स्वयं के कुएं, टैंक और गांव जल आपूर्ति योजनाएं या जिलापरिषद द्वारा सौंपा गया है</li> <li>3. समय-समय पर खुले कुओं को क्लोरीनेट करें और पानी का शुद्धिकरण करें</li> <li>4. अपने गांवों में सभी घरों को पानी का उचित वितरण सुनिश्चित करें</li> <li>5. परीक्षण के लिए पानी नमूना लें</li> <li>6. ग्राम पंचायत द्वारा सौंपी गई जल आपूर्ति योजनाओं को बनाए रखें</li> </ol>
12.	ईंधन और चारा	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. चारा निर्माण के लिए सहकारी समितियों को व्यवस्थित करें और वित्तीय सहायता प्रदान करें</li> <li>2. चारा के बीज की बेहतर विविधता आपूर्ति</li> <li>3. सूखे के दौरान आपूर्ति चारा।</li> <li>4. चारा निर्माण के लिए समुदाय भूमि आवंटित करें।</li> <li>5. वृक्षारोपण गतिविधियों को शामिल करें।</li> <li>6. समुदाय या पंचायत भूमि में ईंधन लकड़ी के बागानों को बनाए रखें और उनकी रक्षा करें</li> </ol>
13	सड़कें, नालियां और पुल और घाट	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. कार्य समितियों के माध्यम से गांव लिंक सड़कों और गांव लेन का निर्माण</li> <li>2. स्थानांतरित किए गए भवनों के निर्माण और रख-रखाव</li> <li>3. पीएमजीएसवाई सड़क निर्माण परियोजनाओं को तैयार करने में सहायता करें और ग्रामसभा के माध्यम से अनुमोदन प्राप्त करें</li> <li>4. कार्य समिति के माध्यम से कार्यों की गुणवत्ता की निगरानी और पर्यवेक्षण करें</li> </ol>

14	बिजली के वितरण सहित ग्रामीण विद्युतीकरण	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. प्राइम फसल सीजन के दौरान बिजली की आपूर्ति की रिपोर्ट करें</li> <li>2. विद्युतीकरण संचरण खंभों को स्थापित करने के लिए भूमि खोजें</li> <li>3. सड़क रोशनी बनाए रखें और संचालित करें</li> <li>4. बिजली चोरी और अवैध चोरी के खिलाफ सतर्कता और रिपोर्ट का प्रयोग करें</li> <li>5. कृषि के लिए बिजली की आपूर्ति की निगरानी करें और बिजली चोरी और अवैध कनेक्शन की जांच में सहायता करें।</li> </ol>
15.	गैर परंपरागत ऊर्जा	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. गैर-पारंपरिक ऊर्जा उपकरणों जैसे जैव-द्रव्यमान, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा के संभावित स्रोतों की पहचान में ब्लॉक पंचायत सहायता</li> <li>2. गैर परंपरागत ऊर्जा उपकरणों के कामकाज की निगरानी</li> </ol>
16	गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ग्राम सभा की मंजूरी के साथ मनरेगा और अन्य व्यक्तिगत लाभार्थी उन्मुख गरीबी उन्मूलन योजनाओं के तहत लाभार्थियों की पहचान करें</li> <li>2. मनरेगा के तहत वार्षिक कार्य योजना तैयार करें और स्वीकृति दें</li> <li>3. ग्राम सभा के माध्यम से मजदूरी के रोजगार की आवश्यकता वाले गांव में श्रमिकों की पहचान में सहायता करें।</li> <li>4. परियोजनाएं तैयार करें और ग्रामसभा के माध्यम से अनुमोदन प्राप्त करें और ब्लॉक पंचायत से तकनीकी अनुमोदन प्राप्त करें</li> <li>5. कार्यो और परियोजनाओं के निष्पादन के लिए कार्य समिति का गठन</li> <li>6. काम की गुणवत्ता, संपत्तियों की कमाई और मानव दिवस उत्पन्न की निगरानी और पर्यवेक्षण</li> </ol>

17	प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों सहित शिक्षा	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. स्कूल आयु के बच्चों के पूर्ण नामांकन सुनिश्चित करें</li> <li>2. स्कूल की इमारतों को बनाए रखें और मैदान खेलें</li> <li>3. शिक्षकों और छात्रों की नियमित उपस्थिति पर ध्यान सतर्कता और संबंधित को रिपोर्ट करें</li> <li>4. पूर्ण नामांकन और ड्रॉपआउट में कमी के लिए अभियान</li> <li>5. ड्रॉप आउट स्थिति का आकलन करें और इसे कम करने के लिए उचित कार्रवाई शुरू करें।</li> <li>6. स्कूलों में दोपहर भोजन योजना के सफल कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण करें</li> </ol>
18	तकनीकी प्रशिक्षण कौशल विकास /	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. पहचान में सहायता और व्यावसायिक शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण के लिए योग्य उम्मीदवारों की सिफारिश करें</li> </ol>
19	वयस्क और गैर औपचारिक शिक्षा	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. वयस्क शिक्षा और साक्षरता अभियानों में भाग लेने के लिए लोगों को संगठित करने में सहायता करें</li> <li>2. प्रौढ़ शिक्षा केंद्रों के कामकाज में पर्यवेक्षण और सहायता और शिक्षार्थियों और स्वयंसेवकों की नियमितता सुनिश्चित करें</li> <li>3. वयस्क शिक्षा केंद्रों की कार्यप्रणाली का पर्यवेक्षण और निगरानी करें</li> </ol>
20	पुस्तकालय	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. गांव में और एससी / एसटी इलाकों में पुस्तकालयों और पढ़ने के कमरे का रखरखाव</li> </ol>
21	सांस्कृतिक गतिविधियां	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. राष्ट्रीय एकीकरण, अभियान साक्षरता और स्वच्छता इत्यादि को मजबूत करने के लिए लोक मीडिया का उपयोग करके गांवों में खेल त्यौहारों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को व्यवस्थित करें।</li> <li>2. खेल को बढ़ावा देना और युवा क्लबों को व्यवस्थित करना</li> <li>3. युवा क्लबों के गठन में सहायता करें</li> <li>4. खेल के मैदानों का विकास।</li> <li>5. सांस्कृतिक केंद्रों की स्थापना</li> </ol>
22	बाजार और मेले	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. गांव मेले और साप्ताहिक बाजार बनाए रखें</li> <li>2. शॉपिंग परिसरों का निर्माण</li> </ol>

23	स्वास्थ्य स्वच्छता	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. गांव स्वास्थ्य समितियों के गठन में सहायता करें</li> <li>2. गांव स्वच्छता, सड़कों और जल निकासी की सफाई का रखरखाव</li> <li>3. स्वच्छता शौचालयों के निर्माण समन्वय और पर्यवेक्षण</li> <li>4. क्लोरिनेट गांव टैंक और कुएं और डीडीटी की छिड़काव</li> <li>5. व्यक्तिगत स्वच्छता शौचालय के निर्माण में सहायक</li> <li>6. महामारी के प्रकोप की रिपोर्ट</li> <li>7. मातृ बाल देखभाल, परिवार नियोजन और टीकाकरण कार्यक्रमों के प्रचार में सहायता करें</li> <li>8. आंगनवाड़ी के रख-रखाव और पर्यवेक्षण में सहायता करें।</li> <li>9. एएनएम और आंगनवाड़ी श्रमिकों की गतिविधियों का पर्यवेक्षण करें</li> <li>10. स्वास्थ्य आंकड़े एकत्र करें (जैसे जन्म, मृत्यु आदि)</li> <li>11. मातृत्व लाभ योजना के लिए योग्य गर्भवती महिलाओं की पहचान करें और लाभ प्राप्त करने में उनकी सहायता करें</li> </ol>
24	परिवार कल्याण	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. महिलाओं के बीच अपने अधिकारों के बारे में जागरूकता उत्पन्न करें</li> <li>2. महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा देना</li> <li>3. एनएसएपी और संबंधित योजनाओं के तहत मातृत्व सहायता के लिए लाभार्थियों की पहचान और सिफारिश में सहायता करें</li> </ol>
25	महिला एवं बाल विकास	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. विभिन्न योजनाओं के तहत लाभार्थी मां और बच्चों की पहचान करें</li> <li>2. नियमित स्वास्थ्य जांच के पोषण और आचरण के वितरण में सहायता करें</li> <li>3. आईसीडीएस की कार्यप्रणाली का पर्यवेक्षण</li> </ol>

26	सामाजिक कल्याण, विकलांग और कल्याण के कल्याण सहित	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. विकलांग लोगों की पहचान में सहायता और उनके पुनर्वास के लिए ब्लॉक पंचायत और ग्राम पंचायत के साथ समन्वय</li> <li>2. विकलांग, विधवाओं, विकलांग व्यक्तियों और कृषि मजदूरों को पेंशन की स्वीकृति और वितरण</li> <li>3. जागरूकता पैदा करें और लोगों को नशीली दवाओं के दुरुपयोग के दुष्प्रभावों के बारे में शिक्षित करें</li> <li>4. परामर्श, व्यसन और देखभाल केंद्रों के बाद नशे से लत व्यक्तियों को परामर्श दे</li> </ol>
27	एससी और एसटी के कल्याण	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. समूह के छात्रों को लक्षित करने के लिए स्कूल वर्दी, किताबें और अन्य सामग्री वितरित करें</li> <li>2. हॉस्टल के रखरखाव में सहायता करें</li> </ol>
28	सार्वजनिक वितरण प्रणाली	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. उचित मूल्य दुकानों के कार्य पद्धति की समीक्षा</li> <li>2. सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रति सतर्कता निकाय के रूप में कार्य करें</li> <li>3. कार्ड, बोगस कार्ड की सूची से पहचानें और इसे राजस्व विभाग को सूचित करें</li> <li>4. उचित मूल्य दुकानों के लिए आवश्यक वस्तुओं के आवंटन आदेश प्रदर्शित करें</li> <li>5. आवश्यक वस्तुओं के प्रति कार्ड और कीमतों के क्वांटम का विवरण प्रदर्शित करें</li> </ol>
29	सामुदायिक संपत्ति का रखरखाव	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. स्थानीय प्रकृति की सभी सामान्य संपत्ति अच्छी हालत में रखें</li> <li>2. ग्राम पंचायतों में सांप्रदायिक भूमि के सभी विवरणों के साथ एक रजिस्टर बनाए रखें</li> <li>3. अतिक्रमण को रोकें और समुदाय संपत्ति के गलत उपयोगों को रोकें</li> <li>4. सामुदायिक हॉल का निर्माण और रखरखाव</li> </ol>

**ग्राम सभा के दौरान सीमावर्ती श्रमिकों / लाईन विभागों द्वारा प्रस्तुतिकरण की मॉडल संरचना**

विभाग के सीमावर्ती श्रमिकों द्वारा प्रस्तुतिकरण के लिए सूचक विचार-विमर्श के मुद्दे :

1. विभाग के संबंधित योजनाओं की संक्षिप्त समीक्षा प्रस्तुत करेंगे जिसमें योग्यता प्रक्रिया, पात्रता तथा योजना के अंतर्गत होने वाले लाभ, ग्राम पंचायत की भूमिका सूचित करना और जीपीडीपी में सम्मिलित करना आदि शामिल है।

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना के अंतर्गत अनुमत गतिविधियाँ	लाभभोगी चयन हेतु पात्रता मापदंड	योजना के अंतर्गत लाभ एंटाइटेल्मेंटस

2. चालू वित्तीय वर्ष (19-2018) में आरंभ की गई गतिविधियाँ और समय सीमा के साथ अभी तक की गई प्रगति

क्र.सं.	गतिविधि का नाम	लाभभोगियों की सूची	गतिविधिवार स्थिति रिपोर्ट						
			प्रगति स्थिति			समयसीमा		निधि उपयोग की स्थिति	
			पूरी हुई गतिविधि	प्रगति पर	आरंभ नहीं की गई	योजना बद्ध समयसीमा	वास्तविक समयसीमा	आबंटित निधियाँ	उपयोग की गई निधियाँ

3. अगले वित्तीय वर्ष गतिविधियाँ प्रस्तावित में (20-2019)

क्र. सं.	चालू गतिविधियों की निरंतरता	आरंभ की जाने वाली नई गतिविधियाँ	कार्रवाई की प्रस्तावित योजना

4. इस सूचना की प्रति ग्राम सभा के दौरान लाईन विभागों के सीमावर्ती श्रमिकों द्वारा पंचायत सचिवों को दी जाएगी।

## सत्र 4

# ग्राम पंचायत और ग्राम सभा की बैठकों की सुविधा

### सत्र उद्देश्य:

- ग्राम पंचायत बैठक आयोजित करना
- ग्राम सभा की बैठक आयोजित करना
- जीपीडीपी के लिए विशेष ग्राम सभा के लिए सुझाए गए एजेंडा मद

### सत्र संक्षिप्त:

- ग्राम पंचायत घास के मूल लोकतांत्रिक संस्थान ग्रामीण क्षेत्रों में समस्त विकास के लिए समन्वित समुदाय कार्रवाई के लिए जिम्मेदार हैं।
- पंचायत निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार है, जैसे - योजनाओं और बजट को मंजूरी देना, विकास गतिविधियों की प्रगति की समीक्षा करना आदि।
- ग्राम सभा ई बांडी कॉरपोरेट है जिसमें सभी व्यक्ति शामिल हैं जिनके नाम गांव स्तर पर पंचायत के लिए चुनावी रोल में शामिल हैं
- सरपंच कानूनी रूप से ग्राम सभा की बैठकों को व्यवस्थित करने के लिए बाध्य है। यह हर साल सरकार द्वारा निर्धारित तारीखों पर निर्धारित की गई प्रक्रियाओं के अनुसार आवश्यक समय पर कम से कम दो ग्राम सभा बैठकों का आयोजन करने के लिए सरपंच का एक अनिवार्य कर्तव्य है।

### सत्र सामग्री:

**4.1 ग्राम पंचायत बैठक आयोजित करना:** पंचायत निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार है, जैसे - योजनाओं और बजट को मंजूरी देना, विकास गतिविधियों की प्रगति की समीक्षा करना आदि। ग्राम पंचायत के सभी वार्ड सदस्यों से ग्राम पंचायत बैठकों में भाग लेने की उम्मीद है। ग्राम पंचायत सरपंच ग्राम पंचायत बैठक की अध्यक्षता करते हैं। पंचायत सचिव बैठक आयोजित करने और आयोजित करने में ग्राम पंचायत सरपंच की सहायता करता है। हर राज्य ने ग्राम पंचायत की बैठकों के संचालन के लिए राज्य पंचायत राज अधिनियम के तहत सांविधिक नियम तैयार किए हैं। ग्राम पंचायतों की बैठकों को सामान्य बैठक और विशेष बैठक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

**क) सामान्य बैठक-** ग्राम पंचायत के कार्यालय में ऐसी तारीख को मिलती है और इस तरह सरपंच राज्य पंचायत कानूनों के तहत फैसला कर सकती है।

**ख) विशेष बैठक -** पंचायत के अधिकांश सदस्यों द्वारा मांग की प्राप्ति के एक सप्ताह के भीतर सरपंच किसी भी समय ग्राम पंचायत की एक विशेष बैठक को बुला सकता है। एजेंडा और बैठक का समय सरपंच द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। इसके अलावा, ग्राम पंचायतों की सामान्य बैठकें और विशेष बैठक राज्य कानूनों के प्रावधानों के अनुसार आयोजित की जाएगी।

#### **4.2 ग्राम पंचायत बैठक में चर्चा के लिए विषय**

ग्राम पंचायत बैठकों में चर्चा करने के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण विषय हैं:

1. पेयजल, स्वच्छता, आवास, आजीविका, स्वास्थ्य और शिक्षा इत्यादि के बारे में पंचायत के विभिन्न वार्ड और लोगों की जरूरत है।
2. स्थानीय लोगों की जरूरतों को पूरा करने और उनकी समस्याओं को हल करने की रणनीतियां
3. ग्राम पंचायत वार्षिक योजना और बजट की स्वीकृति
4. पंचायत की आय / संसाधनों को बढ़ाने के तरीके
5. वार्षिक योजना, बजट और इसके कार्यान्वयन और उपयोग की समवर्ती समीक्षा।
6. मासिक आय-व्यय रिपोर्ट
7. चल रही योजनाओं की प्रगति
8. स्कूलों, आंगनवाड़ी, स्वास्थ्य केंद्र, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों जैसे - गांव संस्थानों की कार्यप्रणाली आदि।
9. नए कार्यों / योजनाओं की स्वीकृति
10. ग्राम सभा में उठाए गए मुद्दे या संकल्प
11. ग्रामसभा सदस्यों की शिकायतें
12. निरीक्षण और लेखा परीक्षा रिपोर्ट का अनुपालन
13. स्थायी समितियों द्वारा उठाए गए मुद्दे

**4.3 ग्राम पंचायत बैठकों के संचालन के लिए प्रक्रिया:** एजेंडा बनाने, नोटिस की सेवा करने, कार्यवृत्त की रिकॉर्डिंग आदि में ग्राम पंचायत सचिव की भूमिका निभानी है। प्रत्येक वार्ड सदस्य को बैठक के बारे में पहले से सूचित किया जाना चाहिए। ग्राम पंचायत के साथ काम करने वाले विभिन्न अधिकारियों को भी बैठक में आमंत्रित किया जा सकता है और आवश्यकता के अनुसार परामर्श किया जा सकता है। आम तौर पर, आम सहमति या बहुमत के वोट द्वारा निर्णय किए जाने हैं। ग्राम पंचायत बैठकों के संचालन के लिए सामान्य प्रक्रिया नीचे दी गई है।

### क) बारंबारिता

- बैठक हर महीने कम से कम एक बार ग्राम पंचायत के कार्यालय में आयोजित की जानी चाहिए
- सरपंच द्वारा तारीख, समय, स्थान तय किया जाना है। सचिव को एजेंडा बुक में लिखना चाहिए और सरपंच द्वारा प्रति हस्ताक्षर करना चाहिए।
- ग्राम पंचायत सरपंच को एक विशेष बैठक आयोजित करनी चाहिए यदि ग्राम पंचायत की मौजूदा सदस्यों में से कम से कम एक तिहाई ग्राम पंचायत बैठक के लिए लिखित में मांग करे।

### ख) सूचना

- कम से कम सात दिन की लिखित सूचना दी जानी चाहिए (विशेष बैठक के मामले में 3 दिन)
- ग्राम पंचायत सचिव नोटिस पर हस्ताक्षर करता है।
- लिखित नोटिस और एजेंडा ग्राम पंचायत के प्रत्येक सदस्यों को आमंत्रित किया जाना चाहिए और नोटिस और नोटिस की प्राप्ति रिकॉर्ड के लिए रखी जानी चाहिए।
- नोटिस ग्राम पंचायत कार्यालय नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किया जा सकता है, क्योंकि ब्लॉक पंचायत को देय सूचना दी जाएगी।

### ग) एजेंडा

- बैठक के एजेंडे में निम्न शामिल हो सकते हैं:
- पिछली बैठक के प्रस्तावों पर अनुवर्ती कार्रवाई
- योजना और बजट, यदि इन्हें मंजूरी दी जाती है
- चल रही योजनाओं की शारीरिक और वित्तीय प्रगति की समीक्षा
- मासिक आय-व्यय रिपोर्ट
- निरीक्षण और लेखा परीक्षा रिपोर्ट के अनुपालन पर चर्चा
- स्थायी समितियों द्वारा उठाए गए मुद्दे
- कोई अन्य प्रासंगिक मुद्दा

### घ) कोरम

- ग्राम पंचायत की कुल संख्या का एक-तिहाई कोरम बनता है, जो बैठक के लिए जरूरी है।
- बैठक की शुरुआत के निर्धारित समय से एक घंटे के भीतर कोरम का गठन नहीं होने पर बैठक स्थगित कर दी जानी चाहिए। इस मामले को सचिव द्वारा उपस्थिति रजिस्टर और मिनट बुक में देखा जाना चाहिए और सरपंच द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए।
- स्थगित बैठक के मामले में, अगली बैठक राज्य नियमों के तहत तय किए गए दिनों के भीतर आयोजित की जानी चाहिए जहां कोरम की आवश्यकता नहीं है।

#### ड.) उपस्थिति और कार्यवृत्त का अभिलेखन

- एक उपस्थिति-सह-कार्यवृत्त रिकॉर्डिंग रजिस्टर को ग्राम पंचायत सचिव द्वारा बनाए रखा जाना चाहिए, जिसमें हर मौजूदा सदस्य को सरपंच की उपस्थिति में अपना नाम हस्ताक्षर करना चाहिए।
- बैठक के मिनट उसी उपस्थिति-सह-मिनट रजिस्टर में दर्ज किए जाने चाहिए
- बैठक समाप्त होने से पहले बैठक के कुछ कार्यवृत्त को पढ़ा जाना चाहिए
- बैठक में अध्यक्ष ग्राम पंचायत सरपंच को उसके बाद उनके सभी हस्ताक्षर प्रस्तुत किए जाने वाले सभी वार्ड सदस्यों की सहमति से कार्यवृत्त को प्रमाणीकृत करने के साथ अपना हस्ताक्षर देना चाहिए ।

#### च) निर्णय लेने

- सरपंचो को बैठक को यथासंभव भागीदारी के रूप में बनाना आवश्यक था
- चर्चा की गई सभी मुद्दों को यथासंभव सर्वसम्मति से तय किया जाना चाहिए
- अभिमत के अंतर के मामले में, मामला वोट में रखा जाना चाहिए, और बहुमत निर्णय जीतना चाहिए
- संकल्प के लिए या उसके खिलाफ मतदान करने वाले सदस्यों के नामों के साथ-साथ प्रत्येक प्रस्ताव को मिनट पुस्तक में दर्ज किया जाना चाहिए।
- वोटों की समानता के मामले में, बैठक के अध्यक्ष के पास दूसरा या निर्णायक मत होगा।
- सरपंच या किसी अन्य सदस्य को किसी अन्य सदस्य के लिए उसकी ओर से उसकी अनुपस्थिति या अनुपस्थिति में मतदान करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए ।

#### छ) ग्राम पंचायत संकल्प

- ग्राम पंचायत संकल्प, ग्राम पंचायत की बैठकों में किए गए निर्णय हैं।
- संकल्पों के माध्यम से, ग्राम पंचायत योजना, बजट, कर और शुल्क, कार्य की मंजूरी और व्यय की मंजूरी और लाभार्थियों के चयन आदि पर निर्णय लेने के फैसले को मंजूरी दे दी है।

**4.4 ग्राम सभा:** ग्राम सभा ई बॉडी कॉरपोरेट है जिसमें सभी व्यक्ति शामिल हैं जिनके नाम गांव स्तर पर पंचायत के लिए चुनावी रोल में शामिल हैं। यह शब्द अनुच्छेद 243 (ख) के तहत भारत के संविधान में परिभाषित किया गया है। ग्राम सभा पंचायती राज प्रणाली का प्राथमिक निकाय है और अब तक का सबसे बड़ा हिस्सा है। यह एक स्थायी निकाय है । पंचायती राज के अन्य सभी संस्थान ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत और जिलापरिषद जैसे निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा गठित किए जाते हैं जबकि ग्राम सभा मतदाताओं की सभा है। ग्राम सभा द्वारा उठाए गए निर्णयों को किसी अन्य निकाय द्वारा रद्द नहीं किया जा सकता है। ग्रामसभा के फैसले को रद्द करने की शक्ति केवल ग्रामसभा के पास ही है।

**4.5 ग्रामसभा के सदस्य:** 18 वर्ष से कम आयु के सभी लोग ग्रामसभा के सदस्य नहीं हैं। व्यक्ति, जो 18 साल से ऊपर हैं और गांव में रहते हैं लेकिन ग्राम पंचायत (जीपी) मतदाता सूची में दाखिला नहीं लेते हैं, वे भी ग्रामसभा के सदस्य नहीं हैं।

**4.6 ग्रामसभा का आयोजन:** सरपंच की मंजूरी मिलने के बाद पंचायत सचिव को ग्राम सभा का आयोजन करना चाहिए। ग्राम पंचायत सरपंच को ग्राम सभा की बैठक आयोजित करना पड़ता है जब ग्राम सभा के 10% सदस्य या ग्राम सभा के 50 व्यक्ति (जो भी अधिक हो) ग्राम सभा आयोजित करने के लिए अपनी मांग जमा करते हैं, हालांकि, उन सदस्यों को बैठक के उद्देश्य को सूचित करना होता है। बैठक की तारीख से 5 दिन पहले बैठक के लिए बैठक के लिए एक लिखित अनुरोध सरपंच को सौंप दिया जाना चाहिए। यदि सरपंच निर्धारित तारीख पर बैठक आयोजित करने में विफल रहता है, तो बैठक करने का अनुरोध करने वाले सदस्य स्वयं ग्राम सभा की बैठक आयोजित कर सकते हैं।

**4.7 ग्रामसभा में सरपंच की भूमिका:** सरपंच कानूनी रूप से ग्रामसभा की बैठकों को व्यवस्थित करने के लिए बाध्य है। हर साल सरकार द्वारा निर्धारित तिथियों पर कम से कम दो ग्राम सभा सभा आयोजित करने के लिए सरपंच का अनिवार्य कर्तव्य है। ग्राम सभा की बैठक के संबंध में सरपंच की जिम्मेदारियों में शामिल हैं:

1. ग्राम सभा की बैठक के कार्यवृत्त को रिकॉर्ड करने के लिए पंजीकृत रजिस्टर पर हस्ताक्षर करें।
2. सदस्यों द्वारा ग्राम सभा में उठाए गए प्रश्नों का उत्तर दें।
3. यह सुनिश्चित करें कि ग्राम पंचायत बैठकों में प्राथमिकता के आधार पर ग्राम सभा की बैठक में किए गए सुझावों पर चर्चा की जाती है।
4. ग्रामसभा प्रस्तावों पर उचित कार्रवाई शुरू करने के लिए सक्रिय भूमिका निभाएं।
5. समाज के सभी वर्गों को मुख्य रूप से, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला इत्यादि सुनिश्चित करने के लिए सभी उपायों का पालन करें, ग्राम सभा में भाग लें जिसमें चर्चाएं हों।

**4.8 ग्रामसभा में पंचायत सचिव की भूमिका:** ग्रामसभा में पंचायत सचिव की भूमिका महत्वपूर्ण है। पंचायत सचिव के कर्तव्यों में शामिल हैं:

- क) सरपंच के परामर्श से ग्राम सभा के एजेंडे को अंतिम रूप देना।
- ख) ग्रामसभा बैठक की सूचना जारी करना।
- ग) व्यापक रूप से ग्रामसभा बैठक विवरण, जैसे - तारीख, समय और स्थान का प्रचार करना।
- घ) पिछली ग्राम सभा की बैठक के प्रस्तावों पर कार्यवाही रिपोर्ट तैयार करना।

ड.) वर्तमान ग्राम सभा की बैठक से पहले एजेंडा वस्तुओं पर नोटों की तैयारी ।

ग्रामसभा की बैठक में भाग लेने वाले लोगों के लिए उचित बैठने, पेयजल सुविधाएं और स्वच्छता सुविधाएं प्रदान करना

**4.9 ग्रामसभा की अनुसूची:** राज्य पंचायत राज अधिनियमों के अनुसार, ग्राम सभा की साल में कम से कम दो से छह बार बैठक चाहिए। लोगों की सुविधा के लिए, अधिकांश राज्यों में, इन राष्ट्रीय बैठकों के लिए चार राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय दिनों को संदर्भ तिथियों के रूप में निर्धारित गया है। ग्राम पंचायत भी उनकी सुविधा के अनुसार अन्य तिथियों पर ग्राम सभा आयोजित करने के लिए स्वतंत्र हैं।

**4.10 ग्राम सभा का स्थान और समय:** ग्राम सभा सभी सदस्यों के बैठने के लिए सुविधाजनक स्थान पर जीके दायरे में आयोजित की जानी चाहिए। जीपी के तहत कई गांवों के मामले में, ग्राम सभा दूसरे गांवों में एक एक करके आवर्तन आधार पर आयोजित की जा सकती है। ग्राम सभा किसी भी समय दिन में यानी सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त से पहले आयोजित की जा सकती है।

**4.11 सभा की अधिसूचना:** ग्रामसभा का आयोजन करने से पहले, राज्य पंचायती राज अधिनियम के अनुसार नोटिस जारी करना महत्वपूर्ण है और प्रचार की व्यापक सीमा सुनिश्चित की जानी चाहिए। सभी मतदाताओं को नियत तारीख से कम से कम एक सप्ताह पहले ग्राम सभा का नोटिस प्राप्त करना होगा। ग्राम सभा की तारीख, समय, स्थान और एजेंडा का जिक्र नोटिस में करना जरूरी है। ग्राम सभा की नोटिस का प्रचार ढोल बजाकर और पंचायत भवन, स्कूलों तथा स्थानीय बाजार के जगहों में नोटिस चिपकाकर भी किया जा सकता है। ग्राम सभा के एजेंडा को स्पष्ट और सरल भाषा में लिखा जाना चाहिए ताकि लोग इसे आसानी से समझ सकें।

**4.12 ग्रामसभा की गणपूर्ति :** ग्राम सभा की बैठक की गणपूर्ति ग्राम पंचायत बैठक के सदस्यों / मतदाताओं का दसवां हिस्सा होगा। यदि पहली बैठक गणपूर्ति के अभाव में स्थगित कर दी गई है तो बैठक किसी अन्य तारीख को स्थगित कर दी जाएगी और प्रक्रिया राज्य के प्रावधानों के अनुसार होगी।

**4.13 जीपीडीपी के लिए विशेष ग्राम सभा का आयोजन (2 अक्टूबर 2014 से):** जीपीडीपी के लिए विशेष ग्राम सभा आयोजित करने का प्रारूप निम्नानुसार है।

1. ग्राम पंचायत के सरपंच / प्रधान ग्राम सभा को बैठक के उद्देश्य के बारे में जानकारी देंगे।
2. ग्राम पंचायत सचिव जीपीडीपी के दृष्टिकोण के बारे में चर्चा करेंगे।

3. श्रेणी मानदंड और सुविधाप्रदाताओं द्वारा मिशन अंत्योदय के तहत संग्रहित डेटा की प्रस्तुति और सत्यापन
4. ग्राम सभा के समक्ष गरीबी से संबंधित मुद्दों और गरीबी न्यूनीकरण की योजनाओं के बारे में एक प्रस्तुति देने के लिए स्वयं सहायता समूह / गांव संगठन।
5. मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण से उभरे अंतरालों पर चर्चा करने और तीन वर्गों में अर्थात् गंभीर रूप से महत्वपूर्ण, उच्च प्राथमिकता और वांछनीय प्राथमिकताओं को वर्गीकृत करने के लिए ग्राम सभा।
6. अनुसूची XI में सूचीबद्ध 29 विषयों से संबंधित लाइन विभागों से सीमावर्ती श्रमिकों द्वारा संविधान के अनुच्छेद 243 जी के अनुसार पंचायतों को समर्पित किया जाना है।
7. वर्तमान वर्ष की गतिविधियों और निधि उपयोग की समीक्षा।
8. वित्त वर्ष 2019-2020 के दौरान ग्राम पंचायत को उपलब्ध संसाधनों पर चर्चा।
9. ग्राम सभा अंतराल के कारणों पर चर्चा कर सकती है और हस्तक्षेप का प्रस्ताव दे सकती है
10. पहचान किए गए अंतराल के आधार पर, जीपीडीपी में शामिल गतिविधियों जैसे कि संपत्ति निर्माण, संपत्ति रखरखाव, कम लागत / कोई लागत नहीं (उदाहरण के लिए 100% टीकाकरण के लिए सामुदायिक संगठन, स्कूल छोड़ना बंद ओडीएफ / ओडीएफ प्लस, सामाजिक सद्भाव, सामाजिक मुद्दों पर जागरूकता आदि) को प्राथमिकता देने के लिए ग्राम सभा,।
11. अंतर विश्लेषण और प्राथमिकता के आधार पर, ग्राम पंचायत जीपीडीपी के तहत गतिविधियों को अंतिम रूप देना।
12. जल आपूर्ति, स्वच्छता प्रबंधन, मल निकासी और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, तूफान जल निकासी, सामुदायिक संपत्तियों का रखरखाव, सड़कों का रखरखाव, फुटपाथ, सड़क बिजली, दफन और श्मशान भूमि आदि जैसी बुनियादी नागरिक सेवाओं के वितरण से संबंधित गतिविधियां। केवल एफएफसी आवंटन से योजना बनाई जाएगी।
13. ग्राम सभा विकास गतिविधियों की प्राथमिकता सूची पर एक प्रस्ताव पारित करेगी। संकल्प ग्राम सभा के सामने पढ़ा जाना चाहिए और तदनुसार दर्ज किया जाना चाहिए।
14. ग्राम सभा के जियो-टैग किए गए तस्वीरों और लोक सूचना बोर्ड के जियो-टैग की गई तस्वीरों को जन योजना अभियान पोर्टल पर अपलोड किया जाना है।
15. सुविधाकर्ता को अपनी रिपोर्ट को निर्धारित प्रारूप में ऑनलाइन अपलोड करने की आवश्यकता है।

**4.14 सामुदायिक संगठन :** समुदाय में सबसे मूल्यवान संसाधन जनता स्वयं ही है। वे गांव के विकास के बारे में निर्णय ले सकते हैं। गांव में उपलब्ध संसाधनों की पहचान और उपयोग करने के लिए समुदाय की एक महत्वपूर्ण भूमिका है।

ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों में भागीदारी दृष्टिकोण के लिए समुदाय संगठन महत्वपूर्ण है। यह स्थानीय निर्णय में ग्रामीण गरीबों की भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। समुदाय के संगठन का मूल विचार समुदाय आधारित संगठनों की समस्या निवारण और कार्यात्मक क्षमताओं को मजबूत करना है। समुदाय समूहों को उनके संसाधनों का प्रभार लेने और यह तय करने के लिए समर्थन दिया जाता है कि कैसे हैं इनका उपयोग किया जाना है। लंबे समय तक सामुदायिक संगठन का मुख्य उद्देश्य सेवा प्रदाताओं और सेवाओं के साधकों के बीच अंतर को खत्म करना और तर्कसाध्य संवाद और कार्य संबंध स्थापित करना है। स्थानीय समुदाय केवल प्राप्तकर्ताओं के बजाय साझेदार बन जाते हैं।

**4.15 ग्रामसभा के लिए लोगों को गतिशील बनाना:** गांव विकास योजनाओं की तैयारी करते समय, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अन्य कमजोर वर्गों के लोगों के उत्थान के लिए ध्यान देना चाहिए। ग्राम पंचायत को ग्राम सभा में व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करना है और उन्हें अपनी भावनाओं और शिकायतों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने का अवसर प्रदान करें। उनकी बेहतर भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के निवास क्षेत्रों में ग्राम सभा के संचालन के बारे में जानकारी व्यापक रूप से प्रचारित की जानी चाहिए। यदि अगली ग्राम सभा की बैठक से पहले उनकी शिकायतों का निवारण किया जाता है, तो ग्राम सभा पर उनका विश्वास बढ़ेगा और वे नियमित रूप से ग्राम सभा की बैठकों में भाग लेने के लिए अधिक रुचि दिखाते हैं।

**4.16 महिलाओं की भागीदारी:** आम तौर पर, ग्रामसभा में महिलाओं की उपस्थिति बहुत अपर्याप्त होती है, और यदि वे उपस्थित होते हैं, तो उन्हें अपनी राय व्यक्त करना मुश्किल होता है और अनुकूलपरिस्थितियों की कमी के कारण उनकी समस्याएं सामने आती हैं। हालांकि महिला स्व-सहायता समूहों ने गांव स्तर के समूहों में गठित हैं और बचत, ऋण इत्यादि जैसे मुद्दों पर बातचीत कर रहे हैं, फिर भी वे ग्रामसभा में खुले तौर पर भाग लेने में संकोच कर रहे हैं। इन परिस्थितियों में, ग्राम पंचायत को पहल करनी चाहिए और एसएचजी और ग्राम संगठनों के माध्यम से सक्रिय प्रचार द्वारा ग्राम सभा में महिलाओं की व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करना चाहिए। इसे महिला वार्ड सदस्यों की सहायता से लिया जा सकता है। महिलाओं की विशिष्ट समस्याओं पर चर्चा की जानी चाहिए और उन्हें हल करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। ग्रामसभा में निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं को शामिल करने के लिए, ग्रामसभा की बैठकों से पहले अलग-अलग महिला ग्राम सभा आयोजित की जानी चाहिए। यह महिलाओं से संबंधित मुद्दों के उचित समाधान सुनिश्चित करता है।

2 अक्टूबर 2018 के बाद जन योजना अभियान (जीपीडीपी) के लिए विशेष ग्राम सभा के सूचक कार्यसूची मद परिशिष्ट में दिए गए हैं।

## परिशिष्ट

जब योजना अभियान (जी. पी. डी. पी.) हेतु विशेष ग्राम सभा के सुझावक एजेंडा मद

<b>जी पी डी पी हेतु विशेष ग्राम सभा के आयोजन हेतु मॉडल अनुसूची सबकी योजना सबका विकास</b>		
		बैठक तिथि----- बैठक स्थान-----
ग्राम सभा----- खंड तालुका-----	जिला-----	एल जी डी कोड----- राज्य-----
<p>★ बैठक की कार्यसूची (.पी.डी.पी.जी) अभियान योजना जन :</p> <p>★ बैठक के लिए सदस्यों स्थिति की पदाधिकारों और प्रतिनिधियों निर्वाचित ,</p> <p>★ ग्राम सभा के आयोजन हेतु प्रोफार्मा</p> <p>(i) ग्राम पंचायत के सरपंच बताएंगे संक्षिप्त में बारे के उद्देश्य के बैठक की सभा ग्राम प्रधान/ (ii) ग्राम पंचायत जी पी डी पी के सचिव विजन के बारे में चर्चा करेंगे (iii) रैंकिंग पैरामीटर की प्रस्तुति और सत्यापन और सुविधाकर्ताओं द्वारा मिशन अंत्योदय के तहत एकत्रित डेटा। (है नहीं मान्य से पहले में सभा ग्राम पिछले यदि) (iv) गांव संगठन गरीबी और मुद्दों संबंधित से गरीबी पहले से सभा ग्राम को समूहों सहायता स्वयं (वीओ) कम करने की योजनाओं के बारे में एक प्रस्तुति देना होगा। (v) ग्राम सभा मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण से उभरने वाले अंतराल पर चर्चा करना और प्राथमिकताओं को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत करना जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण, उच्च प्राथमिकता (vi) संविधान के अनुच्छेद 243 जी के अनुसार अनुसूचित जनजाति में सूचीबद्ध 29 विषयों से संबंधित लाइन विभागों से सीमावर्ती श्रमिकों द्वारा प्रस्तुतिकरण।</p> <p style="text-align: center;"><b>संविधान के अनुच्छेद 243 जी के अनुसार 29 विषयों की सूची</b></p>		

1. कृषि
2. भूमि सुधार
3. लघु सिंचाई
4. पशुपालन
5. मत्स्य पालन
6. सामाजिक वानिकी
7. लघु वन उत्पादन
8. लघु उद्योग
9. खादी, गांव और कुटीर उद्योग
10. ग्रामीण आवास

11. पेय जल
12. ईंधन और चारा
13. सड़क
14. ग्रामीण विद्युतीकरण
15. गैर परंपरागत ऊर्जा
16. गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम
17. शिक्षा
18. व्यावसायिक शिक्षा
19. वयस्क और गैर औपचारिक शिक्षा
20. पुस्तकालय

21. सांस्कृतिक गतिविधियां
22. बाजार और मेले
23. स्वास्थ्य और स्वच्छता
24. परिवार कल्याण
25. महिला एवं बाल विकास
26. सामाजिक कल्याण
27. कमजोर वर्गों का कल्याण
28. सार्वजनिक वितरण प्रणाली
29. सामुदायिक संपत्ति का रखरखाव

vii) वर्तमान वर्ष की गतिविधियों और निधि उपयोग की समीक्षा।

- viii) वित्त वर्ष 2019 -2020 के दौरान ग्राम पंचायत को उपलब्ध संसाधनों पर चर्चा।
- ix) ग्राम सभा अंतराल के कारणों पर चर्चा कर सकती है और हस्तक्षेप का प्रस्ताव दे सकती है।
- x) पहचान किए गए अंतराल के आधार पर ग्राम सभा जीपीडीपी में शामिल होने वाली गतिविधियों को पहचानने और प्राथमिकता देती है जैसे संपत्ति निर्माण, संपत्ति रखरखाव, कम लागत, या कोई लागत नहीं (उदाहरण के लिए 100% टीकाकरण के लिए सामुदायिक संगठन, स्कूल नहीं छोड़ने, ओडीएफ / ओडीएफ प्लस इसके अलावा, सामाजिक सद्भाव, सामाजिक मुद्दों पर जागरूकता आदि)।
- xi) जीपीडीपी के तहत ग्राम पंचायत गतिविधियों को अंतिम रूप देती है।
- xii) केवल बुनियादी आपूर्ति सेवाओं जैसे जल आपूर्ति, स्वच्छता जिसे में सेप्टिक प्रबंधन, सीवेज और ठोस अवशेष प्रबंधन, तूफान जल निकासी, सामुदायिक संपत्तियों का रखरखाव, सड़कों का रखरखाव, फुटपाथ, स्ट्रीट लाईट, दफन और श्मशान भूमि आदि शामिल है जिसे एफएफसी आवंटन से योजना बद्ध किया जाएगा। XI अनुसूची में सूचीबद्ध 29 विषयों से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों के संबंध में अन्य अनुमोदित गतिविधियां भी जीपीडीपी में शामिल की जानी चाहिए।
- xiii) ग्राम सभा विकास गतिविधियों की प्राथमिकता सूची पर एक प्रस्ताव पारित करेगी। संकल्प ग्राम सभा के समक्ष पढ़ा जाना चाहिए और तदनुसार दर्ज किया जाना चाहिए।
- xiv) ग्राम सभा की जियो-टैग तस्वीरों को जन योजना अभियान पोर्टल पर अपलोड किया जाना है।
- XV) लोक सूचना बोर्ड की जियो-टैग तस्वीरों को जन योजना अभियान पोर्टल पर अपलोड किया जाना है।

## सत्र 5:

# ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) की तैयारी के लिए समर्थन

### सत्र के उद्देश्य :

इस सत्र के अंत में प्रतिभागी सक्षम होंगे:

1. जीपीडीपी की अवधारणा और उद्देश्यों का विकास करना
2. जीपीडीपी बनाने में ग्राम पंचायत को आवश्यक समर्थन की रूपरेखा बनाना

### सत्र का संक्षेप :

- व्यय के प्रमुख हिस्से में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के तहत सामाजिक क्षेत्र पर होने वाले व्यय का महत्व है। लेकिन गरीबी की बहुआयामी के कारण, अंतर क्षेत्रीय-दृष्टिकोण के माध्यम से निवेश को अनुकूलित करने की आवश्यकता है।
- संविधान के 73 वें संशोधन के बाद, पीआरआई मूल स्तर पर विकास के प्रयासों का तेजी से नेतृत्व कर रहे हैं। हालांकि, वंचितताओं से निपटने के लिए योजना, प्रशासन और संसाधन आवंटन की कई परतों के कारण, समय और स्थान में अक्सर प्रयास किए जाते हैं, जिससे उप-परिणाम प्राप्त होते हैं। इस प्रकार, ग्राम पंचायत के साथ मूल इकाई के रूप में अभिसरण योजना की आवश्यकता है।
- अभिसरण, उत्तरदायित्व और मापनीय परिणामों को मिशन अंत्योदय के तहत रखा गया यह सुनिश्चित करने के लिए कि संसाधनों को प्रभावी रूप से एसईसीसी डाटा के आधार पर हर वंचित घर के लिए स्थायी आजीविका प्रदान करने में प्रभावी ढंग से प्रबंधित किया जाता है।

### सत्र सामग्री

**5.1 ग्राम पंचायत और आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजना:** विकेंद्रीकृत शासन के माध्यम से पंचायती राज प्रणाली भारत में अद्वितीय है जो इसकी संस्कृति और सभ्यता का एक अभिन्न हिस्सा बन गई है। 73 वें संवैधानिक संशोधन ने निर्वाचित स्थानीय सरकारों के रूप में पंचायती राज संस्थानों (पीआरआड.) को संस्थागत रूपलाईन प्रदान की और इस प्रकार मूल स्तर के लोकतंत्र को मजबूत किया। इसने लोगों की भागीदारी के माध्यम से सुशासन प्राप्त करने

और पारदर्शिता, प्रतिक्रिया, समानता, दक्षता और उत्तरदायित्व को सक्षम करने के लिए शक्तियों के कार्यात्मक और वित्तीय विकेन्द्रीकरण पर जोर दिया।

### **संविधान के अनुच्छेद 243 जी प्रदान करता है:**

"पंचायत की शक्तियां, अधिकार और जिम्मेदारियां.- इस संविधान के प्रावधानों के अधीन, राज्य विधानमंडल, कानून द्वारा, ऐसी शक्तियाँ और अधिकार के पंचायतों को दे सकता है और उन्हें स्वशासन संस्थानों के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हो है और इस तरह के कानून में पंचायतों पर उचित स्तर पर शक्तियों और जिम्मेदारियों के विभाजन के प्रावधान हो सकते हैं, इस तरह के परिस्थितियों के अधीन, जैसा कि निर्दिष्ट किया जा सकता है-

- आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाओं की तैयारी;
- ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध मामलों के संबंध में उन दोनों को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाओं के कार्यान्वयन के रूप में कार्यान्वित किया जा सकता है।"

उपरोक्त प्रावधान का उद्देश्य आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाओं के नियोजन और कार्यान्वयन के लिए ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध उन मामलों सहित शक्तियों और अधिकारों को भंग करने के लिए राज्य सरकारों को सक्षम करके ग्राम पंचायतों (जीपी) को सशक्त बनाना है सक्षम बनाता है। यह पंचायतों को करों और निधियों के प्रावधानों को लागू करने की शक्तियों को भी शामिल करेगा।

**5.2 योजना क्या है ?** : योजनाएं समस्याओं को हल करने संस्थानों और जरूरतों से मेल खाने वाले कुछ वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने के सर्वोत्तम तरीकों को व्यवस्थित रूप से ढूंढने की प्रक्रिया है। भारत का संविधान पंचायतों को स्थानीय स्वशासन के संस्थानों के रूप में स्वीकार करता है और उन्हें आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजना तैयार करने के लिए अनिवार्य करता है। इन योजनाओं को समुदाय, विशेष रूप से ग्राम सभा में शामिल होना है।

**5.3 आर्थिक विकास क्या है ?** ग्रामीण क्षेत्रों के संदर्भ में आर्थिक विकास को उन प्रयासों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो आर्थिक बढोतरी और नौकरियों में वृद्धि, निर्माण और उत्पादकता में वृद्धि, कौशल निर्माण और समर्थन करके समुदाय के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना चाहते हैं। आय स्रोत ग्राम पंचायतों को ऐसी गतिविधियों की योजना बनाने की ज़रूरत है जो बाजार पहुंच में सुधार लाएंगे, मूल्यवर्धन को बढ़ावा देंगे और उत्पादक आधारभूत संरचना जैसे बाजार, गोदामों, तालाबों, सिंचाई सुविधाओं आदि का निर्माण करेंगे। ग्राम पंचायत को कृषि, पशुधन, मत्स्य पालन और बागवानी आदि के विकास के लिए विस्तार गतिविधियों की भी व्यवस्था करनी है।

**5.4 सामाजिक न्याय क्या है ?** : सामाजिक न्याय पर विचार किया गया है कि हर कोई समान आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों और अवसरों के योग्य है। यह व्यक्ति और समाज के बीच निष्पक्ष और उचित संबंध बनाए रखने के

बारे में है। सामाजिक न्याय लोगों को जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने और अपनी पूरी क्षमता प्राप्त करने के लिए बुनियादी सामाजिक आर्थिक लाभ प्राप्त करने में सक्षम बनाता है।

**5.5 सहभागी योजना क्या है?** सहभागिता योजना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा गांव के लोग समस्याओं का निदान करके और समाधान खोज कर पहचाने गए सामाजिक-आर्थिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नियोजन का इस्तेमाल करते हैं। सहभागी योजना की पहल करने का सबसे अच्छा तरीका लोगों से, उनकी समस्याएं क्या हैं और वे अपनी समस्याओं के संभावित समाधान के रूप में क्या करते हैं, इसके बारे में लोगों से सीधे पूछना है। यह लोगों के बीच जागरूकता और इच्छा पैदा करेगा जो किसी भी कार्रवाई में भाग लेने के लिए तैयार होंगा।

**5.6 ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) क्या है ?** जीपीडीपी ग्राम पंचायत की विकास योजना है जो एक सहभागिता प्रक्रिया के माध्यम से तैयार की जाती है जिसमें सभी हितधारकों को उपलब्ध संसाधनों के साथ लोगों की जरूरतों और प्राथमिकताओं से मेल खाती हैं। यह योजना ग्रामीणों द्वारा किए गए सहभागिता ग्रामीण मूल्यांकन (पीआरक) तकनीकों का उपयोग करके गांव के व्यापक सर्वेक्षण के माध्यम से तैयार की जाती है। ग्राम पंचायत स्थानीय नागरिकों को बुनियादी सेवाओं के वितरण के लिए जिम्मेदार हैं और गरीब और हाशियेकृत वाले लोगों की असुरक्षितता को संबोधित करते हैं। यह केवल उपलब्ध संसाधनों के कुशल और जिम्मेदार उपयोग के माध्यम से सुविचारित योजनाओं के कार्यान्वयन के माध्यम से हासिल किया जा सकता है। योजना तैयार करने में ग्रामीणों और निर्वाचित प्रतिनिधियों की भागीदारी से ग्राम पंचायत को मदद मिलेगी :

1. गांव के समग्र विकास और सामाजिक और आर्थिक जरूरतों में अंतर को समझें
2. लोगों की अनुभूत जरूरतों का आकलन करें और विकास अंतराल और समस्याओं की परिमाण की पहचान करें
3. गांव में मौजूद मुद्दों और समस्याओं को प्राथमिकता दें
4. उपलब्ध वित्तीय संसाधनों की पहचान करें और उन्हें पहचान की जरूरतों से मेल करें
5. जरूरतों के साथ संसाधनों से मिलान करके समस्याओं का समाधान करने के लिए योजना तैयार करें
6. वैज्ञानिक और सहभागिता तरीके से जीपी विकास योजना तैयार करें
7. अपने नागरिकों को जीपी का प्रत्यक्ष उत्तरदायित्व सुनिश्चित करें

**जीपीडीपी क्या करता है ?:** जीपीडीपी ग्राम पंचायत की विकास योजना है जो एक सहभागिता प्रक्रिया के माध्यम से तैयार की जाती है जिसमें सभी हितधारकों को उपलब्ध संसाधनों के साथ लोगों की जरूरतों और प्राथमिकताओं से मेल किया जाता है। जीपीडीपी तीन आवश्यक चीजें करता है: (i) यह लोगों का दृष्टि प्रदान करता है कि लोग अपने गांव को

किस तरह दिखाना चाहते हैं (ii) यह उस दृष्टि को प्राप्त करने के लिए स्पष्ट लक्ष्य निर्दिष्ट करता है (iii) उन लक्ष्यों तक पहुँचने के लिए कार्य योजना प्रदान करता है।

ग्राम पंचायत स्तर पर योजना निम्नलिखित को सक्षम बनाता है:

1. पंचायतों को विकास योजना तैयार करने के लिए सक्रिय करना और इस प्रकार स्थानीय सरकार के रूप में अपनी पहचान स्थापित करना
2. निर्णय लेने में भाग लेने के लिए लोगों को संगठित और प्रेरित करना जिससे प्रशासन को लोगों के करीब अधिक लाया जा सके
3. प्राथमिकताओं को तय करने के लिए स्थानीय धारणाओं, स्थानीय मुद्दों और विश्लेषण पर चर्चा के लिए एक मंच प्रदान करना
4. लोगों की अनुभूत की जरूरतों और आकांक्षाओं का आकलन करना
5. विकास अंतराल की परिमाण की पहचान करना
6. गांव में मौजूद मुद्दों और समस्याओं को प्राथमिकता देना
7. प्रभावी अभिसरण के माध्यम से सभी उपलब्ध योजनाओं और संसाधनों को लाना
8. विभिन्न क्षेत्रों के क्षैतिज / लंबवत / स्थानिक / लौकिक एकीकरण के लिए प्रदान करना।

जीपीडीपी की तैयारी एक समयबद्ध प्रक्रिया है। जीपीडीपी आदर्श रूप से उपलब्ध या संगठनीय संसाधनों के अनुसार प्राथमिकता से लोगों की जरूरतों, बुनियादी सेवाओं और उनकी आकांक्षाओं से मेल खाना चाहिए। इसे एक सहभागी, समावेशी और पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से तैयार किया जाना चाहिए।

**5.7 स्थानीय योजना में उभरते मुद्दे और चुनौतियां:** संघ और राज्य सरकारों द्वारा जारी दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन के अनुभव और देश भर में पिछले तीन वर्षों में जीपीडीपी के कार्यान्वयन के कार्यान्वयन के अनुभव के आधार पर, कुछ नई चुनौतियों के साथ-साथ अवसर आ गए हैं भविष्य में टिकाऊ विकास और सामाजिक न्याय के लिए इसे ध्यान में रखना आवश्यक है। अन्य बातों के साथ-साथ कुछ महत्वपूर्ण बातें इस प्रकार हैं :

1. योजना प्रक्रिया और ग्राम सभा में अपर्याप्त लोगों की भागीदारी
2. बुनियादी ढांचे के निवेश पर अधिक जोर
3. अपर्याप्त सार्वजनिक सेवा वितरण
4. अपने स्रोत राजस्व का दायरा विस्तारित करना
5. उभरते मुद्दों में पीआरआई की बढ़ती भूमिका
6. पंचायतों की ई-सक्षमता

7. निधियों, योजनाओं और पहलों का अभिसरण
8. सार्वजनिक व्यय में क्षमता और प्रभाव में सुधार करने की आवश्यकता
9. ग्राम पंचायत में भौतिक और वित्तीय डाटाबेस का निर्माण और रखरखाव
10. स्थानिक और क्षेत्रीय योजना के एकीकरण की आवश्यकता 11. योजना के लिए मानव संसाधन और तकनीकी सहायता तक पहुंच
12. पीआरआई की बढी संस्थागत क्षमताओं और ईआर और कार्यकर्ताओं की क्षमता की आवश्यकता
13. ब्लॉक और जिला स्तर पर एकीकृत योजनाओं की आवश्यकता
14. सतत विकास लक्ष्यों को स्थानीय बनाना
15. जलवायु परिवर्तन और समग्र पर्यावरणीय मुद्दों को संबोधित करना
16. प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन का महत्व
17. सामाजिक विकास पर जोर
18. पीआरआई-एसएचजी अभिसरण के रूप में सामाजिक पूंजी का उपयोग करने के लिए विस्तृत दायरा
19. जेंडर, बाल मुद्दों, बुजुर्गों और विकलांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) को एकीकृत करना
20. जेंडर और बाल मुद्दों को एकीकृत करना
21. कुपोषण की रोकथाम
22. मजबूत निगरानी और एमआईएस की आवश्यकता
23. 15 वें वित्त आयोग और राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों का संभावित प्रभाव।

ऊपर सूचीबद्ध सभी विषयों की चुनौतियाँ हैं जिन्हें ग्रामीण स्थानीय सरकारों द्वारा प्रभावी विकेंद्रीकृत भागीदारी योजना के माध्यम से ग्रामीण लोगों की विकास आकांक्षाओं को बढ़ाने और पूरा करने के लिए जीपीडीपी में संबोधित करने और शामिल करने की आवश्यकता है।

**5.8 कार्यकारी समूहों का गठन:** ग्राम पंचायत के पास पहले से ही विभिन्न विषयगत क्षेत्रों के लिए स्थायी / कार्यात्मक समितियाँ हैं (अलग-अलग राज्य में भिन्न हो सकता है)। ग्राम पंचायत जीपीडीपी के विभिन्न फोकस क्षेत्रों पर विषयगत कार्यकारी समूहों का गठन कर सकता है। प्रत्येक कार्यकारी समूह में प्रासंगिक क्षेत्र में विशेषज्ञता रखने वाले विशिष्ट सदस्यों या विशिष्ट विषयों में रूचि रखने वाले सदस्य शामिल होंगे। संबंधित विषयगत क्षेत्रों की स्थायी / कार्यात्मक समिति के अध्यक्ष कार्यकारी समूह की अध्यक्षता करेंगे। संबंधित लाइन विभाग या क्षेत्र के किसी भी स्थानीय विशेषज्ञ के ब्लॉक स्तर अधिकारी संबंधित कार्यकारी समूह के उपाध्यक्ष हो सकते हैं। ये समूह ग्राम पंचायत के समग्र मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण के तहत काम करेंगे। नीचे दिखाए गए अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा कार्यकारी समूह गठित किए जाएंगे। हालांकि, ग्राम पंचायत पर्यावरण संरक्षण, स्थानिक योजना और आपदा प्रबंधन योजना आदि पर कार्य समूह जैसे स्थानीय जरूरतों के आधार पर अधिक कार्यकारी समूहों का गठन कर सकता है।

- क) मानव विकास कार्य समूह: पर्यावरण और स्वच्छता सहित स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों की चर्चा करना।
- ख) महिला एवं बाल विकास कार्य समूह : जेंडर मुद्दे और महिला तथा बाल अधिकार, महिला सशक्तिकरण, अत्याचार / दुर्व्यवहार के विरुद्ध संरक्षण से संबंधित मुद्दों और उनके कौशल विकास संबंधित मुद्दों पर चर्चा करना।
- ग) आजीविका विकास कार्य समूह : कृषि और संबद्ध क्षेत्रों, छोटे मध्यम और कुटीर उद्योगों, उद्यमशीलता, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, मिट्टी और जल संरक्षण, ग्रीन के कवर और जैव-विविधता संबंधी मुद्दों पर चर्चा करना।
- डी) सामाजिक न्याय और सामाजिक सुरक्षा कार्य समूह : अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति समुदायों और विकलांग व्यक्ति (पीडब्ल्यूडी), बुजुर्ग लोग सहित समाज के अन्य पिछड़े वर्गों के विकास से पर चर्चा करना।
- इ.) बुनियादी ढांचा और विविध कार्य समूह : स्थानीय बुनियादी ढांचे और ग्राम पंचायत के लिए प्रासंगिक अन्य मुद्दों से पर चर्चा करना।

**5.9 पर्यावरण निर्माण / आईईसी गतिविधियां:** औपचारिक योजना तैयार करने से पहले, पर्यावरण निर्माण और सामाजिक जुड़ाव होना चाहिए। पर्यावरण निर्माण और गतिविधियों के बीच कौशल के अनुवांशिक परिवर्तन, दृष्टिकोण और पुनः अभिविन्यास लाने के लिए पर्यावरण निर्माण गतिविधियों का बहुत महत्व है। इसलिए, जीपीडीपी प्रक्रिया में पहली गतिविधि ग्रामीणों के बीच जागरूकता पैदा करके नियोजन प्रक्रिया को शुरू करने के लिए ग्राम सभा आयोजित करना है। ग्राम सभा को जीपीडीपी की आवश्यकता के बारे में जागरूक किया जाएगा, चरण-दर-चरण गतिविधियों को नियोजन प्रक्रिया में लिया जाएगा। पूरी योजना प्रक्रिया में परिवार के कम से कम एक सदस्य द्वारा ग्राम सभा समेत आयोजित की जाने वाली आगामी बैठकों में प्रतिनिधित्व और हर परिवार की भागीदारी की आवश्यकता और महत्व समझाया जा सकता है। सुविधाकर्ता को उचित पर्यावरण निर्माण में पहल करनी चाहिए और ग्राम सभा में महिलाओं की व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करना चाहिए। प्रभावी पर्यावरण निर्माण के लिए ग्राम पंचायत द्वारा उठाए जा सकने वाले गतिविधियों की एक स्पष्ट सूची प्रभावी ग्रामसभा की ओर अग्रसर है और इस प्रकार समग्र और व्यापक जीपीडीपी बनाना है जिसे परिशिष्ट 1 में दिया गया है। जीपीडीपी तैयारी के लिए पर्यावरण निर्माण में सभी को कार्रवाई में आकर्षित करने के लिए खुशी का माहौल बनाना चाहिए।

**5.10 डाटा संग्रह:** जीपीडीपी की तैयारी का प्राथमिक उद्देश्य ग्राम पंचायत की विकास आवश्यकताओं को संबोधित करने के तरीकों की पहचान करना और तैयार करना है। इसलिए, स्वास्थ्य, शिक्षा, आजीविका, सुविधाओं की उपलब्धता, सेवाओं और अधिकारों की पूर्ति और हाशिए वाले वर्गों, स्थानीय बुनियादी ढांचे इत्यादि के अधिकारों से संबंधित मुद्दों के बारे में पहली जानकारी प्राप्त करना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। माध्यमिक डेटा के अतिरिक्त, प्राथमिक डाटा संग्रह के लिए माध्यमिक स्रोतों को अद्यतन / सत्यापित करने की आवश्यकता होगी, यदि कोई अंतराल

हो तो भरना और परिवार के प्रत्येक सदस्य की क्षमता के आधार पर व्यक्तिगत घरेलू विकास योजना को सक्षम करने के लिए प्रत्येक घर का 360 डिग्री कवरेज प्राप्त करना। उचित संकलन और संयोजन के बाद दोनों माध्यमिक और प्राथमिक डाटा पैरामीटर के लिए बेसलाइन और उनमें से प्रत्येक में अंतराल को कवर करने के लिए प्रदान करते हैं। प्राथमिक डाटा के संग्रह के लिए उपकरण नीचे वर्णित हैं।

**5.10.1 घरेलू सर्वेक्षण का आयोजन:** यदि ग्राम पंचायत ने कुछ विशिष्ट मुद्दे की पहचान की है जिसके लिए विशिष्ट समूहों जैसे निराशाजनक, अक्षम व्यक्तियों, विधवाओं, संकट प्रवासन या उच्च कुपोषण आदि वाले परिवारों से विवरण प्राप्त करने की आवश्यकता है, तो इन परिवारों के घरेलू सर्वेक्षण किए जा सकते हैं। एक मानक प्रारूप का उपयोग किया जाना चाहिए जिसमें सभी आवश्यक जानकारी शामिल होगी। सुविधाकर्ताओं को यह ध्यान में रखना चाहिए कि केवल आवश्यक जानकारी एकत्र की जाती है ताकि इस डाटा को एकत्र करना एक आसान प्रक्रिया बन जाए। घरेलू सर्वेक्षण आयोजित करते समय, कुछ चीजों को ध्यान में रखा जाना चाहिए:

- क) सर्वेक्षण के लिए तैयार प्रारूप की आवश्यकता होनी चाहिए
- ख) प्रारूप में हस्तक्षेप के आधार पर प्रारूप में बहुत विशिष्ट और संकल्प वाले प्रश्न होना चाहिए
- ग) डाटा को आसानी से एकत्रित करने के लिए केवल आवश्यक जानकारी एकत्र की जाती है।
- घ) सर्वेक्षण की गुणवत्ता का आश्वासन दिया जाना चाहिए

**5.10.2 सहभागिता ग्रामीण मूल्यांकन (पीआरक):** सहभागिता ग्रामीण मूल्यांकन (पीआरक) ग्राम पंचायत में प्रत्यक्ष संसाधन और स्थानीय लोगों के साथ परामर्श के माध्यम से मौजूदा संसाधनों, सेवाओं, बुनियादी ढांचे इत्यादि का आकलन करने के लिए तकनीकों का एक सेट है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो स्थानीय समुदाय को एजेंडा और कार्यवाही की योजना विकसित करने के लिए ग्राम पंचायत में अपनी समस्याओं, संसाधनों, क्षमताओं और प्राथमिकताओं की पहचान करने में सक्षम बनाता है।

**5.10.3 ट्रान्ससेक्ट वॉक :** आवास में एक ट्रान्ससेक्ट वॉक संपत्तियों को विकसित करने की आवश्यकता पहचानने में मदद करता है, उन प्राकृतिक संसाधन जिनको उपयोग किया जा सकता है, विभिन्न सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए भूमि उपलब्ध है और विभिन्न सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच की सीमा हो सकती है। सुविधाकर्ता समुदाय के साथ चर्चा करें और गांव के भीतर विभिन्न परिदृश्यों पर जानकारी एकत्र करें।

**5.10.4 फोकस ग्रुप चर्चा (एफजीडी):** एफजीडी ग्राम पंचायत विकास से संबंधित एक विशिष्ट विषय पर चर्चा करने के लिए समान पृष्ठभूमि या अनुभव से लोगों को इकट्ठा करने का एक साधन है। यह समस्याओं पर लोगों की धारणाओं को समझने में मदद करेगा और संभावित समाधानों के बारे में एक विचार प्राप्त करेगा। ग्राम पंचायत द्वारा निर्णय लेने के लिए विभिन्न महत्वपूर्ण हितधारकों के लिए प्रासंगिक विषयों पर अलग एफजीडी आयोजित किए जा सकते हैं।

**5.10.5 माध्यमिक डाटा:** पहले से एकत्र किए गए डाटा और रिकॉर्ड / रिपोर्ट से उपलब्ध डाटा को माध्यमिक डाटा कहा जाता है। माध्यमिक डाटा के विभिन्न स्रोत हैं :

1. सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना डाटा 2011 (एसईसीग)
2. लाइन विभाग डाटा (कृषि / शैक्षणिक / आवास / स्वास्थ्य)
3. स्वतंत्र अध्ययन / रिपोर्ट से डाटा
4. ग्राम पंचायत की मिशन अंत्योदय डाटा
5. ग्राम पंचायत स्तर जनसांख्यिकी डाटा
6. ग्राम पंचायत स्तर मौजूदा बुनियादी ढांचे
7. पीएचसी / उप-केंद्र स्तर डाटा
8. सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) डाटा
9. आंगनवाड़ी डाटा
10. प्राथमिक स्कूल डाटा
11. एसएचजी / एसएचजी संघ डाटा इत्यादि
12. एसबीएम सर्वेक्षण डाटा।

**5.11 स्थिति विश्लेषण:** स्थिति विश्लेषण ग्राम पंचायत के विभिन्न क्षेत्रों में पहले से एकत्रित माध्यमिक डाटा के विश्लेषण और ग्राम पंचायत में उपलब्ध या विभिन्न माध्यमिक स्रोतों जैसे जनगणना, एसईसीसी डाटा, हाल ही में लाइन द्वारा किए गए विभिन्न सर्वेक्षणों के विश्लेषण के माध्यम से ग्राम पंचायत के विभिन्न क्षेत्रों में मौजूदा विकास की स्थिति का आकलन करता है। विभाग, लाइन विभागों द्वारा प्रकाशित डाटा, पिछले जीपीडीपी सर्वेक्षण आदि। पीआरए से एकत्रित बेसलाइन सर्वेक्षण और जानकारी के माध्यमिक स्रोतों से डेटा का उपयोग करते हुए विभिन्न विकास क्षेत्रों की वर्तमान स्थिति को स्थिति विश्लेषण विप्लेषित और प्रस्तुत किया जा सकेगा। इस प्रकार यह मात्रात्मक डाटा और लोगों की धारणाओं से अंतर्दृष्टि से निष्कर्षों का संश्लेषण होगा। स्थिति विश्लेषण ने आने वाले वर्ष में विकास एजेंडा लेने के लिए ग्राम पंचायत की प्राथमिकताओं को निर्धारित किया। संबंधित लाइन विभाग ग्राम पंचायत को उद्देश्य की स्थिति लेने में सहायता करेंगे। विभिन्न फोकस से संबंधित स्थिति, मुद्दे और चुनौतियां निम्नानुसार होंगी।

1. बुनियादी ढांचे के मामले में, अंतराल की पहचान करें। उदाहरण के लिए, भौतिक संपर्क के संबंध में, सड़कों के बिना बस्तियों को सूचीबद्ध करना ; सड़क की लंबाई की आवश्यकता आदि। इसमें मरम्मत, बहाली उन्नयन और नए निर्माण भी शामिल हो सकते हैं। इसी तरह सिंचाई के लिए, अनियमित क्षेत्रों को चिह्नित किया जाना चाहिए और अधिकतम कवरेज के लिए पहचाने जाने वाले सबसे अधिक लागत प्रभावी प्रणाली - इसमें मौजूदा स्रोतों में सुधार, नए स्रोतों की पहचान, टपकन, सूक्ष्म सिंचाई, जल संचयन और संरक्षण आदि जैसी नई प्रौद्योगिकियों को अपनाना शामिल होगा।

2. सामाजिक विकास के मामले में, मुख्य समस्याओं और मुद्दों की पहचान करें, जिन्हें आम तौर पर माना जाता है और स्वीकार किया जाता है और मुख्य रूप से लोगों की धारणाओं और विशेषज्ञ राय से कारणों को सूचीबद्ध करता है। उदाहरण के लिए जनजातीय विकास के मुद्दों जैसे भूमि अलगाव और गिरावट, कौशल और रोजगार के अवसरों की कमी और सार्वजनिक सेवाओं और सुविधाओं तक पहुंच की कमी के मामले में तेजी से चित्रित और चर्चा की जा सकती है।
3. आर्थिक विकास के मामले में, ध्यान उस संभावित पर होना चाहिए जो उचित और स्थायी रूप से हासिल किया जा सके। उदाहरण के लिए, कृषि निर्माण में वृद्धि, और उत्पादकता, बाजारों से जोड़ने, मूल्य जोड़ आदि पर बाधाओं का आकलन किया जा सकता है।
4. मानव विकास के मामले में, कमियों को मूल्यांकन और संबोधित करने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, शिक्षण के न्यूनतम स्तर को प्राप्त नहीं करने के कारण, ड्रॉपआउट के कारण, कुपोषण के कारणों आदि की पहचान की जानी चाहिए।
5. पारिस्थितिकी और पर्यावरण के मामले में, स्थिरता को प्रभावित करने वाले कारकों की पहचान की जानी चाहिए, उदाहरण के लिए, भूजल की कमी; कृषि भूमि की गिरावट आदि गिरावट का विश्लेषण किया जा सकता है।
6. शासन के मामले में, अक्षमता, अप्रभाविता, देरी, भ्रष्टाचार और अन्य दुर्भावना आदि के कारणों को निर्धारित करने पर जोर देना चाहिए। इसमें ग्राम पंचायत और सथान में अन्य सार्वजनिक संस्थानों को कवर करना चाहिए।
7. नागरिक सुविधाओं के मामले में पर कि क्यों सेवा प्रावधान और वितरण के निर्धारित मानकों को प्राप्त नहीं किया जा रहा है प्रयास करना चाहिए। उदाहरण के लिए, स्वच्छता में, ठोस और तरल अपशिष्ट दोनों के स्तर और उचित तरीके से निपटान नहीं किए जाते हैं, अध्ययन करने की आवश्यकता होती है।

स्थिति विश्लेषण जीपीडीपी में सम्मिलित किए जाने वाले मुद्दों के लिए प्राथमिकताओं को स्थापित करने के लिए आधार बनना है / स्थिति विश्लेषण से, अल्प अवधि में तत्काल क्या करने की आवश्यकता है, और लंबी अवधि में क्या करने की आवश्यकता है पर सुझाव देना चाहिए। इसके अलावा लोग स्वयं क्या करने जैसे व्यवहारिक परिवर्तन, सामुदायिक योगदान इत्यादि - और विभिन्न योजनाओं और वित्त पोषण के स्रोतों के माध्यम से क्या संबोधित करने की आवश्यकता है पर स्पष्टता होनी चाहिए .. संभावित विकास विकल्पों और प्राथमिकताओं की पहचान के लिए परिशिष्ट II में एक उदाहरण दिया गया है।

**5.12 स्टेटस रिपोर्ट का विकास (डीएसआर):** स्थिति विश्लेषण पूरा होने पर, जीपीपीएफटी को ग्राम पंचायत की विकास स्थिति रिपोर्ट तैयार करने की आवश्यकता है जिसे ग्राम सभा के समक्ष रखा जाना है ताकि लोगों को संबंधित फोकस क्षेत्रों में समुदाय के सटीक और वास्तविक समय की स्थिति के बारे में जागरूक किया जा सके। डीएसआर ग्रामीणों को निम्न पहचान करने में मदद करेगा:

1. ग्राम पंचायत के विकास प्रयासों में उपलब्धियों, सीमाओं और अंतराल के संदर्भ में विभिन्न विषयगत क्षेत्रों में ग्राम पंचायत के विकास की स्थिति
2. ग्राम पंचायत के लिए विकास लक्ष्यों को अनुकूलित करने के लिए अभिसरण रणनीतियाँ
3. वार्षिक आधार पर अगले पांच वर्षों में विकास एजेंडा का अधिग्रहण किया जाना चाहिए
4. जिन मुद्दों को ग्राम पंचायत समेत विभिन्न प्राधिकरणों और संस्थानों द्वारा संबोधित किया जाना है

डीएसआर की सूचक रूपलाईन परिशिष्ट III में दी गई है।

**5.13 विजनिंग अभ्यास :** इस चरण में ग्राम सभा आयोजित की जानी चाहिए और डीएसआर के निष्कर्षों के आधार पर विजनिंग से अभ्यास करना है। विजनिंग, आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के संदर्भ में ग्राम पंचायत विकास एजेंडा के मानदंडों को विकसित करने की प्रक्रिया है। यह स्थानीय लोगों को शिनाख्त प्रमुख विषयगत क्षेत्रों में अगले 5 वर्षों में अपने ग्राम पंचायत को क्या करना है कि एक अभिव्यक्ति है। विजनिंग अभ्यास नियोजन में उद्देश्यों को सुनिश्चित करेगा और लोगों को योजना प्रक्रिया के स्वामित्व की भावना जगायेगा। विजनिंग दस्तावेज में ग्राम पंचायत की प्रतिबद्धता को स्पष्ट करना है ताकि बुनियादी कार्यों की मात्रा और गुणवत्ता में सुधार करने के लिए अपने कार्यों को और अधिक प्रभावी और कुशल बनाया जा सके। यह प्राथमिकताओं की पहचान करने और योजना अवधि के दौरान ग्राम पंचायत द्वारा हासिल किए जाने वाले स्पष्ट मील का पत्थर स्थापित करने में भी मदद करता है।

**5.14 आवश्यकताओं की प्राथमिकता:** सुविधाकर्ता स्थानीय विकास में अंतर को भरने के लिए लोगों की आवश्यकताओं की पहचान करने के लिए ग्रामसभा और ग्राम पंचायत बैठकों में विचार-विमर्श की दिशा निर्देशित करेगा। इसे डीएसआर के आधार पर किया जाएगा। जरूरतों की प्राथमिकता को ग्राम पंचायत के सभी वर्गों को कवर करने वाले विभिन्न शिनाख्त विषयगत क्षेत्रों में किया जाएगा।

**5.15 संसाधनों का पहचान / अनुमान:** सभी क्षेत्रों पर डाटा एकत्र किए जाने के बाद, अगला महत्वपूर्ण अभ्यास उपलब्ध वित्तीय संसाधनों का स्टॉक लेना है। संसाधन अनुमान में स्रोतों जो ग्राम पंचायत के आदेश पर उपलब्ध होंगे। की विविधता को ध्यान में रखना है ग्राम पंचायत संसाधन योजना में निम्नलिखित शामिल हैं:

1. कर, उपयोगकर्ता शुल्क और योगदान आदि के माध्यम से अपने संसाधन राजस्व का आकलन और संग्रहण।
2. स्थानीय परोपकारी, एनआरआई, कॉर्पोरेट क्षेत्र और एन जी ओ आदि सहित सामुदायिक योगदान के माध्यम से वित्त पोषण का अभिनव माध्यम।

3. विध्वंस और स्थानान्तरण इत्यादि सहित प्रत्येक योजना के तहत ग्राम पंचायत को किए गए आवंटन के बारे में लाइन विभागों से जानकारी प्राप्त करना।
4. ग्राम पंचायत और केंद्र एवं राज्यों की प्रमुख योजनाओं से अभिसरण के संभावित स्रोत को भी प्रत्यक्ष निधि प्रवाह बहाव

कम से कम 10 से 20% संसाधनों को स्थानीय रूप से एकत्रित किया जाना चाहिए। ग्राम पंचायत फंडों को तीन श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है: अन्तर्निहित निधि, आंशिक अन्तर्निहित निधि (जहां उपयोग में कुछ लचीलापन है) और टाइड निधि। ग्राम पंचायत के अपने संसाधनों के अलावा फंडिंग धाराओं की जानकारी को राज्य और केंद्रीय बजट दस्तावेज, और जिला मिशन के योजना दस्तावेज, और अन्य लाइन विभागों से प्राप्त की जा सकती है। विभिन्न स्रोतों से ग्राम पंचायत में आने वाली सभी फंडिंग धाराओं को एक साधारण रूप से सूचीबद्ध किया जा सकता है। ग्राम पंचायत के विभिन्न प्रकार के संसाधन परिशिष्ट IV में दिखाए जाते हैं।

**5.16 पंचायत विकास संगोष्ठी:** मसौदा स्थिति रिपोर्ट तैयार करने के बाद, विकास के मुद्दों और उपलब्ध संसाधनों पर और विचार-विमर्श के लिए एक दिन पंचायत विकास संगोष्ठी आयोजित की जानी चाहिए। सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों, ग्राम पंचायत कार्यकर्ता, ब्लॉक स्तर पर कार्यरत रहे लाइन विभागों के अधिकारी, विषय विशेषज्ञ विशेषज्ञ, कार्यकर्ता, एसएचजी, सीबीओ, ग्राम पंचायत स्तर पर काम कर रहे सीएसआर / एनजीओ के प्रतिनिधियों और स्थानीय संसाधन व्यक्तियों को सेमिनार में आमंत्रित किया जाना है। सुविधाकर्ता टी सेमिनार में डीएसआर प्रस्तुत करेगा और प्रतिक्रिया एवं सुझाव आमंत्रित करेगा। प्रत्येक फोकस क्षेत्र में वर्तमान स्थिति, स्थानीय जरूरतों, संसाधनों और विकास विकल्पों पर विस्तार से चर्चा की जानी चाहिए। संगोष्ठी में स्थानीय स्तर की योजनाओं और परियोजना विचारों की पुष्टि की जानी चाहिए। परामर्श से जरूरी मसौदे रिपोर्ट में परिवर्तन को पंचायत द्वारा औपचारिक रूप से अनुमोदित किया जाना होगा। अंतिम रिपोर्ट ग्रामसभा / पंचायत समिति में रखी जानी है।

**5.17 योजना के लिए संसाधनों का मैचिंग :** मसौदा योजना को स्थिति रिपोर्ट, क्षेत्रवार प्राथमिकता आवश्यकताओं और संसाधनों के विषयगत समूहवार आवंटन के आधार पर तैयार किया जाना चाहिए। ग्राम पंचायत विकास योजना आदर्श संसाधनों के साथ लोगों की जरूरतों और प्राथमिकताओं से मेल खाती है। ग्राम पंचायत को अपने संसाधनों को सर्वोत्तम संभव उपयोग में रखने का प्रयास करना चाहिए। प्रत्येक आवश्यकता को वित्त पोषण के स्रोत से जोड़ा जाना चाहिए। यह उपलब्ध संसाधनों को मैट्रिक्स में रखकर किया जा सकता है। यह मैट्रिक्स ग्राम पंचायत को प्राथमिक आवश्यकताओं से मेल खाने में मदद करता है ताकि धन उपयोग से जुड़ी सशर्तता पूरी हो सके। संसाधनों को निम्नलिखित चरणों के माध्यम से योजना से मैच किया जा सकता है।

**चरण 1: प्रत्येक आवश्यकता को एक मैट्रिक्स में वर्गीकृत करना :** डाटा संग्रहण और दृष्टि अभ्यास, आवास, स्कूल, पोषण, सड़कों, स्वास्थ्य देखभाल जैसी आवश्यकताओं को प्रदान करेगा। इनमें से प्रत्येक को धन के स्रोत के बावजूद विस्तृत फोकस क्षेत्रों के तहत वर्गीकृत करने की आवश्यकता होगी।

**चरण 2:** विशिष्ट उद्देश्य अनुदानों को सौंपना : आवश्यकताओं को वर्गीकृत करने के बाद, अगला कदम बंधे अनुदानों की पहचान करना होगा जो उन आवश्यकताओं को संबोधित करेगा और प्रत्येक आवश्यकता के लिए इन संसाधनों को मैच करेगा

**चरण 3:** भाग-संयुक्त फंडों को सौंपना : एमजीएनआरजीए और XIV वित्त आयोग निधि जैसे कुछ उद्देश्यों के लिए उपलब्ध भाग - संयुक्त निधि को अन्य योजनाओं के साथ एकत्रित किए जा सकते हैं। इन फंडों का उपयोग सीमाओं के भीतर अंतराल भरने के लिए किया जा सकता है।

**चरण 4:** पूरी तरह से संघटित धनराशि सौंपना : अंतिम चरण जहां धन के अन्य स्रोत उपलब्ध नहीं हैं। सबसे महत्वपूर्ण अंतराल को भरने के लिए पूरी तरह से संघटित धन की नियुक्ति करना है ये राजस्व के अपने स्रोत हैं, और राज्य गैर-योजना अनुदान और राज्य वित्त आयोग हस्तांतरण द्वारा जारी किए गए सामान्य उद्देश्य अनुदान हैं। लाइन विभागों, सार्वजनिक और दाताओं और सीएसआर फंडों से योगदानों को मिलाकर बड़े पैमाने पर कोशिश की जा सकती है। सभी कार्यों के लिए निर्माण और परिणामों को स्पष्ट रूप से अनुमान लगाना भी आवश्यक है। कार्यान्वयन और परिणामों के लिए प्रारंभ किए जाने वाले प्रस्तावित प्रत्येक क्रियाकलाप को पेश किया जाना चाहिए।

**5.18 लागत रहित या बिना लागत / कम लागत विकास:** ग्राम पंचायत द्वारा की जाने वाली कई योजनाबद्ध गतिविधियाँ लागत गहन लागत नहीं हो सकती या कोई धन की आवश्यकता नहीं हो सकती है। वास्तव में पंचायत कई संग्रहण गतिविधियों शुरू कर सकती है जो अधिकतर कम लागत या बितना लागत के हो सकती। कम लागत / बिना लागत विकास प्रक्रिया के लिए सामुदायिक संग्रहण और सामुदायिक स्वामित्व महत्वपूर्ण है। परिशिष्ट V में कम लागत / बिना लागत वाली गतिविधियों की एक स्पष्ट सूची दी गई है।

**5.1.9 पांचवीं अनुसूची क्षेत्रों में जीपीडीपी के लिए विशेष प्रक्रिया:** अनुसूचित क्षेत्रों अधिनियम 1 99 6 (पीईएसक) के पंचायत विस्तार के प्रावधान क्षेत्र के सभी विकास कार्यक्रमों की योजना और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए ग्राम सभा के माध्यम से स्थानीय समुदायों के सशक्तिकरण का समर्थन करता है। भूमि अधिग्रहण, बसाना और पुनर्वास, भूमि बहाली (अलगाव के मामले में), खनिजों का खनन, मादक द्रव्यों का उपयोग, लघु वन उपज का स्वामित्व, ग्राम बाजारों का जल निकायियों प्रबंधन, और धन उधार पर नियंत्रण के क्षेत्रों में लोगों की भागीदारी और सहमति की भी समर्थन की जाती है। इसलिए, पांचवीं अनुसूची क्षेत्रों में ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करते समय इस कानून की भावना का पालन किया जाना चाहिए। पांचवीं अनुसूची के तहत क्षेत्रों में ग्राम पंचायत के मामले में, नागरिकों की भागीदारी बस्ती / स्तर पर सुनिश्चित की जानी चाहिए। इन योजनाओं को बस्ती / ग्राम के स्तर पर तैयार करने के बाद, इन योजनाओं को बिना किसी संशोधन के ग्राम पंचायत स्तर पर एकीकृत किया जाना चाहिए।

**5.20 ड्राफ्ट जीपीडीपी की तैयारी और इसकी स्वीकृति :** डीएसआर की ग्राम सभा में विचार-विमर्श के बाद, प्राथमिकताओं को सूचीबद्ध करना और संसाधन लिफाफा को ध्यान में रखते हुए एक मसौदा ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार की जानी चाहिए। प्रत्येक फोकस क्षेत्रों शिनाख्त कार्यों, निधि आवंटन, कार्यों को पूरा करने के लिए समय लाईन का संकेत देते हुए विकास योजनाओं को तैयार करते समय, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के लोगों के उत्थान के लिए विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। आयोजित होने वाले विकास सेमिनार में इस मसौदे की रिपोर्ट पर विस्तार से चर्चा की जानी चाहिए। विकास संगोष्ठी से उत्पन्न फीडबैक और सुझावों को शामिल करने के बाद, ड्राफ्ट जीपीडीपी, अंतिमकरण और अनुमोदन पर चर्चा के लिए ग्राम पंचायत की विशेष बैठक आयोजित की जानी चाहिए। ग्राम सभा द्वारा मंजूरी दी गई जीपीडीपी ग्राम पंचायत द्वारा कार्यान्वयन के लिए अपनाई जाएगी। जीपीडीपी की तैयारी के लिए ग्राम पंचायत एक व्यापक और सरल प्रारूप का पालन कर सकता है। ग्राम पंचायत संबंधित राज्य द्वारा निर्धारित राज्य-विशिष्ट प्रारूप का भी पालन कर सकते हैं। ड्राफ्ट ग्राम पंचायत विकास योजना का मॉडल अध्यायकरण परिशिष्ट VI में दिया गया है।

**5.21 योजना कार्यान्वयन:** एक बार जीपीडीपी को मंजूरी मिलने के बाद, योजना के समय पर और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं होनी चाहिए। अभिसरण योजना के कार्यान्वयन में कई हितधारक हैं, और कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार कई कार्यकर्ता के पास ग्राम पंचायत के साथ संस्थागत इंटरफ़ेस नहीं हो सकता है.. इसलिए जीपीडीपी के सुचारू कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित कार्रवाई की जा सकती है: -

1. विशेष रूप से निर्धारित समय सीमाओं के भीतर सार्वजनिक कार्यों के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न विभागों, एजेंसियों और कार्यकर्ताओं की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए और अधिकारियों को नाम और पदनाम द्वारा व्यक्तिगत कार्य को सौंपा जा सकता है।
2. परिचालन समस्याओं को हल करने, लोगों की समस्याओं को सुनने और शिकायतों को दूर करने के लिए ग्राम पंचायत डीपी के विभिन्न घटकों के कार्यान्वयन पर चर्चा करने के लिए प्रचारित अनुसूची के अनुसार सभी संबंधित लोगों के लिए अवसर प्रदान करने के लिए सभी गांव स्तर के अधिकारियों / कार्यकर्ताओं को नियत दिनों पर ग्राम पंचायत में आने के लिए एक प्रणाली रखा जाना चाहिए।
3. पेयजल आपूर्ति, स्वच्छता, स्वास्थ्य, पोषण, स्कूली शिक्षा, जलागत वानिकी आदि से संबंधित स्थानीय समितियों और आंगनवाड़ी, स्कूलों, स्वास्थ्य केंद्रों आदि जैसे स्थानीय संस्थानों में ग्राम पंचायत की भूमिका को समझाते हुए संबंधित विभागों के साथ विस्तृत परिपत्र जारी किए जाए।
4. सामुदाय संग्रहण संयुक्त रूप से लाभार्थियों और स्थानों का चयन, परिसंपत्तियों का संचालन और प्रबंधन, सामुदाय करार सेवाओं की डिलीवरी के लिए अंतिम मील संयोजन प्रदान करने के विशेष संदर्भ के साथ कार्यान्वयन में सीबीओ के लिए स्पष्ट भूमिका प्रदान की जाए।

**5.22 क्षमता निर्माण:** जीपीडीपी की तैयारी और कार्यान्वयन के पूरे अभ्यास में व्यापक क्षमता निर्माण सबसे महत्वपूर्ण कारक है। प्रत्येक राज्य को क्षमता निर्माण के लिए एक स्पष्ट रणनीति और कार्यवाही की योजना विकसित करना है। एसआईआरडी / पीआरटीआई जैसे राज्य स्तरीय संस्थान क्षमता निर्माण कार्यक्रम को प्रारंभ करेगा। प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लक्षित समूह को उन कार्यों के आधार पर पहचाना जाना चाहिए जिनकी उन्हें उम्मीद है। प्रमुख लक्ष्य समूह में निर्वाचित प्रतिनिधियों, पीआर अधिकारी, लाइन विभाग के कार्यकर्ताओं, एसएचजी नेटवर्क, सीबीओ के सदस्य, विभिन्न ग्राम के स्तरीय समितियों के सदस्य, विभिन्न योजनाओं के तहत पहचाने गए स्वयंसेव और एमजीएनआरईजीएस टीमों के सदस्य आदि को शामिल किया जाएगा।

**5.23 उत्तरदायित्व प्रणाली:** कार्य के विभिन्न चरणों की निगरानी करने के लिए योजना शुरू करने से कार्यों के लिए किए गए व्यय को रिकॉर्ड करने तक एक समग्र प्रणाली स्थापित करने की आवश्यकता है। इस उद्देश्य के लिए, चायत एंटरप्राइज़ सूट (पीईएस) के सभी अनुप्रयोगों का उपयोग करना आवश्यक है। जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित उपायों को अपनाया जाना है:

1. संसाधन लिफाफा, पीआरए अभ्यास, स्थिति विश्लेषण और विजनिंग, प्राथमिकता के लिए अपनाए गए मानदंड, और स्थान / लाभार्थियों की पहचान के लिए मानदंड और अनुमोदित योजना के विवरण और अपेक्षित परिणामों के विवरण का व्यापक प्रकटीकरण
2. स्रोत व्यक्तियों और विभिन्न कार्यबलों एवं समितियों के सदस्यों के नाम का प्रकटीकरण
3. यह सुनिश्चित करना कि जितना संभव हो उतने नागरिकों की उपस्थिति में व्यापक प्रचार के बाद ग्राम पंचायत की प्रमुख बैठकें आयोजित की जाती हैं
4. ग्राम पंचायत में सुविधाजनक स्थानों में नागरिक सूचना बोर्ड / दीवार पेंटिंग स्थापित किया जाना और वेबसाइटों पर उपर्युक्त जानकारी अपलोड करना चाहिए
5. संबंधित सांसदों और निर्वाचन क्षेत्र के विधायकों को सूचित करने के लिए योजना तैयार करने पर चर्चा करने के लिए ग्राम सभा बैठकें की सूचना
6. ग्राम सभा की भू - टैग की गई तस्वीरों को लोगों के अभियान पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा और सार्वजनिक सूचना बोर्डों पर प्रदर्शित किया जाएगा
7. नागरिकों के लिए एक शिकायत निवारण प्रणाली उपलब्ध होनी चाहिए
8. उद्देश्यों को प्राप्त करने में प्रगति सहित विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में, ग्राम पंचायत की उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए प्रमुख योजनाओं का सामाजिक लेखा परीक्षा कि जाएगा।

**5.24 दिशा पोर्टल:** आधारभूत संरचना के सुधार और मानव विकास एवं देश के लोगों के कल्याण में सुधार के लिए बड़ी संख्या में महत्वपूर्ण कार्यक्रम लागू किए जा रहे हैं। जिलों और देश के कुशल और समयबद्ध विकास के लिए संसद, राज्य

विधानसभा और स्थानीय सरकारों के सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने के उद्देश्य को पूरा करने की दृष्टि से जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति (दिशा) का गठन किया गया है। ये समितियां निर्धारित प्रक्रियाओं और दिशानिर्देशों के अनुसार कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की निगरानी कर सकती हैं और अधिक प्रभाव के लिए तालमेल और अभिसरण को बढ़ावा दे सकती हैं। दिशा केन्द्रीय, राज्य और स्थानीय सरकारों को सौंपे गए जिम्मेदारियों की निगरानी और विकास समन्वयन को सुधारेगा। दिशा भारत सरकार की सभी गैर-सांविधिक योजनाओं को कवर करेगा जो सामान्य रूप से प्रशासित होते हैं। दिशा पोर्टल में सूचीबद्ध योजनाएं परिशिष्ट VII में दी गई हैं।

### परिशिष्ट।

#### ग्राम पंचायत स्तर पर पर्यावरण सृजन के लिए गतिविधियों की एक स्पष्ट सूची

1. जीपीडीपी के बारे में सूचित करते हुए और प्रक्रिया में भाग लेने के लिए उन्हें आमंत्रित करने के लिए सभी परिवारों का पत्र।
2. कार्यकारी समूह के सदस्यों को पत्र, अन्य स्थानीय प्रतिष्ठित व्यक्ति की नियोजन प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी चाहते हुए।
3. आकर्षक नारे के साथ दीवार पर लेखन, पुस्तिकाओं का वितरण, बैनर का प्रदर्शन, सार्वजनिक पते की घोषणा के साथ पोस्टर।
4. छात्रों, स्वयंसेवकों, एसएचजी / सीबीओ सदस्यों, आदि सहित ग्रामीणों द्वारा रैलियाँ / अभियान
5. स्ट्रीट स्थानीय लोक या लोकप्रिय मीडिया / कलाकारों द्वारा स्ट्रीट प्ले।

6. प्रदर्शनों द्वारा पंचायत दिवस समारोह का आयोजन और गाँव के बुजुर्गों और सामुदायिक नेताओं, विशेष रूप से महिलाओं, स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों का सम्मान करना।
7. खुल में शौच से मुक्त / स्तनपना सप्ताह / एड्स जागरूकता / वृक्षारोपण जैसे विभिन्न जागरूकता सप्ताह मनाना।
8. गाँव को कैसे मॉडल गाँव बनाया जा सकता है पर स्कूल और कॉलेज के छात्रों और ग्रामीणों के बीच चित्रकारी और साहित्यिक प्रतियोगिताएँ।
9. ग्राम पहचान गीत बनाना और प्रभातफेरी और अन्य बैठकों में गाना।
10. गाँव की भावना को प्रतिबिंबित करने वाले ग्राम खेल और लोक कला त्योहारों और विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन करना एवं विभिन्न त्योहारों और अवसरों के लिए ग्राम गीत का चयन करना।
11. प्रत्येक बच्चे, विशेष रूप से लड़कियाँ स्कूल में है और विशेष जरूरतों वाले बच्चों के लिए विशेष सुविधाएं प्रदान की जाती हैं को सुनिश्चित करने के लिए युवा समूहों का आयोजन करना,।
12. सड़कों, नालियों, स्कूल और पंचायत परिसर की सफाई, वृक्षारोपण जैसे समुदाय स्वैच्छिक गतिविधियों का आयोजन करना।
13. वृद्ध व्यक्तियों द्वारा चर्चा और स्थानीय इतिहास पर प्रदर्शनी का आयोजन करना।
14. गाँव और उसके इतिहास और विशेषता के बारे में एक वृत्तचित्र फिल्म तैयार करना।
15. स्कूली बच्चों के साथ-साथ स्कूल से बाहर के लिए स्कूल नामांकन शिविर। हुए बच्चों एवं स्कूल बैग, वर्दी और अन्य किटों का वितरण।
16. रोजगार मेले का आयोजन और शिक्षा एवं कौशल के लिए बेरोजगार युवाओं के रूचि के क्षेत्र का रूप रेखा तैयार करना।
17. प्रधान मंत्री जन धन योजना जैसे वित्तीय समावेशन शिविर का आयोजन।
18. विभिन्न उन्नत कृषि मशीनीकरण, कृषि में आईसीटी, कृषि विपणन, मिट्टी परीक्षण और नकद फसलों के महत्व पर जागरूकता पैदा करने के लिए किसानों हेतु कृषि मेला आयोजित करना।

## परिशिष्ट II

### स्थिति विश्लेषण विकास विकल्प का एक उदाहरण उदाहरण

क्र.सं	समस्या की पहचान	स्थिति विश्लेषण	संभावित विकास विकल्प
	सार्वजनिक स्थानों में स्वच्छता की कमी	खराब जल निकासी सुविधा रखरखाव की कमी के कारण सामुदायिक शौचालयों का विघटन खुले में शौच स्वच्छता अभ्यास के बारे में जागरूकता की कमी वीएचएससी गठित नहीं	नई जल निकासी लाइन का निर्माण बेहतर समुदाय शौचालयों का निर्माण खुले शौचालय और खराब स्वच्छता प्रथाओं के परिणामों पर जागरूकता पैदा करना। गांव के स्वास्थ्य और स्वच्छता समिति को सक्रिय करना
	कम फसल उत्पादकता	उच्च नस्ल किस्मों के बारे में जागरूकता की कमी। आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकियों को कम अपनाना फसल संरक्षण उपायों की कमी	बेहतर कृषि प्रथाओं पर जागरूकता पैदा करना। अनाज, दालें और सब्जियों की उच्च नस्ल किस्मों का परिचय। उन्नत कृषि-खेतों / कृषि विज्ञान केंद्र में एक्सपोजर का दौरा। कृषि प्रथाओं के बारे में कृषि विभाग के साथ समय समय पर बातचीत।
	एससी बच्चों में कुपोषण	गर्भवती महिलाओं और बच्चों को संतुलित आहार की कमी। आजीविका से पोषण भोजन पर खराब व्यय पैटर्न रसोई बागवानी का कोई अभ्यास नहीं	संतुलित आहार भोजन की आवश्यकता के बारे में जागरूकता पैदा करना। वीएचएससी को मजबूत किया जाना है। पौष्टिक सब्जियों / फलों के स्रोत के रूप में रसोई उद्यान को प्रोत्साहित करना।
	गुणात्मक शिक्षा की कमी	गुणात्मक शिक्षण विधियों और सामग्रियों की कमी। ग्राम शिक्षा समिति द्वारा शिक्षकों की निगरानी नहीं	शिक्षण की गुणवत्ता की निगरानी के लिए एसएमसी को मजबूत किया जाना है। शिक्षण सहायक उपकरण की आपूर्ति वैज्ञानिक प्रयोगशाला के लिए नए उपकरण की खरीद की जाएगी
	जानवरों के लिए अपर्याप्त गुणात्मक चारा	चारा भूमि पर अतिक्रमण के कारण चारा मात्रा में कमी खाद्य तैयारी और चारा की खेती के बारे में जागरूकता की कमी चारे की खेती को बढ़ाने के लिए सिंचाई जल की अपर्याप्तता	मिनी किट वितरण के माध्यम से चारा की खेती के लिए बेहतर किस्मों का परिचय। कृषि सीमा पर चारा वृक्षारोपण गुणवत्ता फ्रीड तैयार करने और फोरेज फसल की खेती पर किसान प्रशिक्षण / फ्रंट लाइन अनुकरण
	प्रतिबंधित संस्थागत विकास प्रक्रिया	एसएचजी अवधारणा के बारे में जागरूकता की कमी। विभिन्न सरकारी एजेंसियों से ऋण योजनाओं के बारे में जागरूकता की कमी। कोई गांव स्तर संघ / विकास समिति नहीं	संस्थागत विकास प्रक्रिया / प्रबंधन एसएचजी पर अधिक एसएचजी का गठन ऋण के लिए वित्तीय संस्थानों के साथ संबंध विकसित करना।

## परिशिष्ट III

विकास स्थिति रिपोर्ट की सूचक रूपलाईन (डीएसआर)

**भाग I** - स्थिति मूल्यांकन की प्रक्रिया / पद्धति का विवरण।

**भाग II** - स्थिति विश्लेषण के आधार पर अपनी सामाजिक-आर्थिक स्थिति को चित्रित करने वाले ग्राम पंचायत की एक प्रोफ़ाइल।

**भाग III** - पिछले 3-5 सालों से ग्राम पंचायत विकास एजेंडा के अंतर विश्लेषण सहित विकास हस्तक्षेपों का मूल्यांकन।

1. आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन
2. मानव विकास
3. सामाजिक विकास
4. पारिस्थितिकीय विकास
5. लोक सेवा वितरण
6. सुशासन
7. एसडीजी
8. स्किलिंग
9. महिला और बाल संरक्षण और विकास
10. ई सक्षमता
11. आधारभूत संरचना की स्थिति।

**भाग IV** - लोगों की भागीदारी और स्वामित्व पर विवरण। इसे और सुधारने के लिए सुझाव

**भाग V** - संसाधनों की स्थिति आरओएसआर समेत संसाधन लिफाफे का विस्तार करने के लिए दायरा।

**भाग VI** - ग्राम पंचायत के विकास परिणामों को अनुकूलित करने में मानव, वित्तीय और प्राकृतिक संसाधनों के संदर्भ में अभिसरण अवसर।

**भाग VII** - संभव हस्तक्षेप के क्षेत्रवार व्यापक विचार।

**भाग VIII** - निष्कर्ष

**भाग IX** - परिशिष्ट (पीआरए मानचित्रों की प्रतियां, प्रश्नावली प्रारूप, तस्वीरें और अन्य प्रासंगिक दस्तावेज)

## परिशिष्ट IV

## ग्राम पंचायत के आदेश पर धन के स्रोत

### क) एकीकृत संसाधन

1. राज्य वित्त आयोग अनुदान
2. करों, गैर कर, किराए, बाजारों और तालाबों के लिए शुल्क, उपयोगकर्ता शुल्क इत्यादि जैसे राजस्व का अपना स्रोत।

### ख) आंशिक रूप से बंधे धन

1. एमजीएनआरईजीएस
2. 14 वें वित्त आयोग अनुदान
3. सामुदायिक योगदान (नकद रूप में श्रम)
4. कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी निधि / एनजीओ योगदान दयालु और नकदी में
5. राज्य योजनाएं
6. कोई अन्य स्रोत

### ग) बंधे संसाधन

1. स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम)
2. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम)
3. ग्राम पंचायत को आवंटित अन्य केंद्रीय / राज्य प्रायोजित योजना निधि

## परिशिष्ट V

### लागत -रहित कम या कोई लागत नहीं - कम लागत विकास

1. टीकाकरण कवरेज: 100% टीकाकरण कवरेज के लिए स्वयंसेवकों (एसएचजी, युवा समूह इत्यादि) के माध्यम से जागरूकता सृजन
2. एसएचजी समूह और अन्य सीबीओ एवं एन जी ओ के माध्यम से शून्य अपशिष्ट गांव के लिए जागरूकता सृजन
3. स्कूलों में 100 प्रतिशत नामांकन: जागरूकता निर्माण और सामुदायिक निगरानी
4. आंगनवाड़ी में 100 प्रतिशत नामांकन
5. गांव में शून्य परती भूमि: सामूहिक खेती के लिए एसएचजी का जुड़ाव
6. पारिवारिक अपशिष्ट जल प्रबंधन के लिए सोक पिट निर्माण के लिए जागरूकता सृजन प्रशिक्षण।
7. आंगनवाड़ी और रसोई उद्यान के माध्यम से कुपोषण को दूर करना
8. बाल श्रम उन्मूलन के लिए सामुदायिक कार्रवाई
9. सामुदायिक देखभाल देने वाले समूह: जागरूकता सृजन और संग्रहण के माध्यम से विस्तार पडे मरीजों के लिए ऐसे समूहों का गठन ।
10. प्रेरणा और व्यवहार परिवर्तन ।
11. सरकार के उच्च स्तरों द्वारा प्रदान की गई विभिन्न सेवाओं का उपयोग और उपयोग को सुविधाजनक बनाना ।
12. आर्थिक गतिविधियों में विचारों और प्रौद्योगिकियों का प्रसार ।
13. एसएचजी के तहत आर्थिक गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करना ।

## परिशिष्ट VI

### मसौदा ग्राम पंचायत विकास योजना का मॉडल अध्याय

#### क) ग्राम पंचायत की मूल रूपरेखा (डीएसआर के आधार पर)

ग्राम पंचायत रूपरेखा, सूचना, सामाजिक-आर्थिक मानकों, आजीविका डाटा, प्राकृतिक संसाधन, ग्राम संस्थान, निर्वाचित सदस्यों की सूची, पंचायत कर्मचारियों की सूची इत्यादि।

#### ख) ग्राम पंचायत स्तर समितियां और उप समितियां

1. स्थायी समितियों की सूची -
2. विकेंद्रीकृत योजना तैयारी से संबंधित सुविधाकर्ता / कार्यकारी समूहों की सूची
3. गांव के स्तर पर स्रोत व्यक्तियों के नाम
4. ग्राम पंचायत कार्यालय में जीपीडीपी के प्रभारी कार्यकर्ताओं के नाम और पदनाम
5. अन्य सरकारी कार्यकर्ता / सहायक कर्मचारी जो जीपीडीपी का भाग है उनके नाम।

#### ग) जीपीडीपी के लिए प्रारंभ गतिविधियां

1. ग्राम सभा बैठकें
2. हितधारक परामर्श
3. कार्यकारी समूह बैठकें
4. संसाधन समूह बैठकें
5. योजना के अंतिमकरण पर ग्राम पंचायत बैठकें

#### घ) विकास स्थिति (डीएसआर का सारांश)

#### ड.) ग्राम पंचायत के लिए निर्धारित विजनिंग वक्तव्य और लक्ष्य

#### च) संसाधन लिफाफा

#### छ) वार्षिक योजना और कार्यान्वयन रणनीति

#### ज) परिशिष्ट:

1. ग्राम सभा बैठकों की कार्यवृत्त
2. कार्यकारी समूहों की रिपोर्ट (ओं)
3. स्थिति विश्लेषण रिपोर्ट (ओं)
4. योजना स्वीकार अनुमोदित करते हुए ग्राम पंचायत के मिनट / संकल्प।

## परिशिष्ट VII

### दिशा पोर्टल पर विभिन्न योजनाओं की सूची

- 1 चौदहवीं वित्त आयोग - मूल अनुदान और प्रदर्शन अनुदान
- 2 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस)
- 3 प्रधान मंत्री आवास योजना (ग्रामीण)
- 4 राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी)
- 5 दीनदयाल अपध्याय - ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाड.)
- 6 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम)
- 7 राष्ट्रीय रूरबन मिशन (एनआरयूएम)
- 8 दीनदयाल अंत्योदया योजन (डे-एनआरएलएम)
- 9 प्रधान मंत्री ग्रामीण सडक योजना (पीएमजीएसवाड.) या ग्रामीण संयोजकता (आरग)
- 10 राष्ट्रीय ग्रामीण पेय जल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी)
- 11 स्वच्छ भारत मिशन - ग्रामीण (एसबीएम-ग्रामीण)
- 12 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाड.)
- 13 प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाड.) - एकीकृत जलागत प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी)
- 14 प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाड.) - हर खेत को पानी (एचकेकेपी)
- 15 भूतल माइनर सिंचाई योजना
- 16 प्रधान मंत्री फासल बीमा योजना (पीएमएफबीवाड.)
- 17 परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाड.)
- 18 मृदा स्वास्थ्य कार्ड (एसएचग)
- 19 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम)
- 20 ई-राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-एनएएम)
- 21 राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम / एनएचएम)
- 22 सर्व शिक्ष मिशन (एसएसएम)
- 23 मध्याह्न भोजन योजना (एमडीएमएस)
- 24 बेटी बाचाओ, बेटी पढाओ (बीबीबीपी)
- 25 एकीकृत बाल विकास योजना (आईसीडीएस)
- 26 प्रधान मंत्री उज्ज्वल योजना (पीएमयूवाड.)
- 27 डिजिटल इंडिया: कॉमन सर्विस सेंटर (सीएसग)
- 28 डिजिटल इंडिया लैंड रि कॉर्ड्स आधुनिकीकरण कार्यक्रम (डीआईएलआरएमपी)
- 29 दीन दयाल अपध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीजीजीवाड.)
- 30 प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना
- 31 प्रधान मंत्री खानजी क्षेत्र कल्याण योजना (पीएमकेकेकेवाड.)
- 32 एकीकृत विद्युत विकास योजना (आईपीडीएस)
- 33 मरम्मत, नवीनीकरण और बहाली योजना
- 34 प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी)
- 35 प्रधान मंत्री आधार ग्राम योजना (पीएमएजीवाड.)
- 36 स्मार्ट सिटी मिशन
- 37 कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन (AMRUT)

- 38 विरासत शहर विकास और वृद्धि योजना (एचआरआईडीएड.)  
 39 दूरसंचार रेलवे, राजमार्ग, जलमार्ग खान, आदि जैसे आधारभूत संरचना संबंधित कार्यक्रम।  
 40 प्रधान मंत्री आवास योजना (सभी शहरों के लिए आवास)  
 41 स्वच्छ भारत मिशन

ग्राम पंचायत प्रदर्शन को मापने के लिए प्रश्नावली (मिशन अंत्योदया सूचकांक)

राज्य कोड	राज्य का नाम	
जिला कोड	जिले का नाम	
सीडी ब्लॉक कोड	सीडी ब्लॉक का नाम	
ग्राम पंचायत कोड	ग्राम पंचायत का नाम	
गांव कोड	गाँव का नाम	गाँव का पिन कोड

I. मूल:

क्र.सं	मुख्य मानदंड	महत्व	टिप्पणि
1.	कुल जनसंख्या		
2.	पुरुष		
3.	महिला		
4.	कुल परिवार		
5.	उन्नत एसएचजी की कुल संख्या		
6.	कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)		
7.	नेट बोया क्षेत्र (हेक्टेयर में)		
8.	कुल अर्षिचित भूमि क्षेत्र (हेक्टेयर में)		
9.	सिंचित क्षेत्र (हेक्टेयर में)	4	>80%=4, 61-80%=3, 41-60%=2, 20-40%=1, <20%=0

II. मुख्य आधारभूत संरचना पैरामीटर्स:

क्र.सं	मुख्य मानदंड	महत्व	टिप्पणि
	आधारभूत संरचना मानदंड		
10.	% परिवार विशेष रूप से लगे हुए हैं		
	क. फार्म गतिविधियों		
	ख. गैर-कृषि गतिविधियां	5	>50%
11.	बैंकों की उपलब्धता (हाँ = 1, नहीं = 2)	5	यदि हां तो 5
12.	यदि गांव में उपलब्ध नहीं है; की दूरी सीमा कोड निकटतम स्थान जहां सुविधा उपलब्ध है; (<3कि.मी.-1; 3-5कि.मी.- 2; 5-10 कि.मी.-3, >10कि.मी.-4)		विकल्प के लिए 1- 4; 2-3 3=2, विकल्प 4=0
13.	यदि गांव में बैंक उपलब्ध नहीं है; बैंक / व्यापार की उपलब्धता इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ संवाददाता?	2	यदि हां और प्रश्न 5 का उत्तर 'नहीं' है
14.	एटीएम की उपलब्धता (हाँ-1;नहीं-2)	1	अगर हाँ
15.	क्या गांव सभी मौसम सड़क से जुड़ा हुआ है (हाँ -1; नहीं-2)	5	अगर हाँ
16.	क्या गांव में एक आंतरिक सीसी / ईट सड़क है	4	अगर हाँ

	(हाँ-1;नहीं-2)		
17.	सार्वजनिक परिवहन की उपलब्धता (बस -1; वैन-2; आटो 3; कोई भी -4)	3	विकल्प 1,2,3 =3 के लिए विकल्प 4=0 के लिए
18.	इंटरनेट कैफे / सामान्य सेवा केन्द्र की उपलब्धता	2	
	(हाँ -1; नहीं -2)		
19.	घरेलू उपयोग के लिए बिजली की उपलब्धता (1-4 घंटे- 1; 5-8 घंटे -2; 9-12 घंटे -3;> 12 घंटे -4; कोई बिजली नहीं -5)	4	विकल्प के लिए 1=1; 2=2; 3=3; 4=4; 5=0
20.	सार्वजनिक वितरण प्रणाली की उपलब्धता (पीडीएस) (हाँ-1;नहीं-2)	1	यदि हों तो
21.	बाजारों की उपलब्धता (मंडी -1; नियमित बाजार-2; साप्ताहिक हाट-3; कोई नहीं -4)	3	विकल्प 1,2 =3 के लिए विकल्प 3=1 के लिए
22.	पाइप द्वारा टैप पानी की उपलब्धता (1) 100% बस्तियों को कवर किया गया (2) 50 से 100% बस्तियों को कवर किया गया (3) <50% निवास को कवर (4) केवल एक आवास कवर किया गया है (50 कवर नहीं है)	4	विकल्प 1 =4 विकल्प 2 =3 विकल्प 3 = 2 विकल्प 4 = 1 विकल्प 5 = 0
23.	टेलीफोन सेवाओं की उपलब्धता (लैंडलाइन -1; मोबाइल -2; दोनों-3; कोई नहीं -4)	2	विकल्प 1,2 ,3=2 के लिए विकल्प 4 =0
24.	स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग करने वाले घर का कुल संख्या (एलपीजी/ जैव गैस)	4	<25% = 1 25%-50%=2 51%-75%=3 >75% =4 साफ ईंधन के साथ कोई घर नहीं है = 0
25.	कच्चा दीवार और कच्चा छत वाले घर की संख्या कच्चा दीवार है ... 1 घास / छाप्पर / बांस आदि 2 प्लास्टिक / पॉलिथिन 3 मिट्टी / कच्चा ईंट 4 लकड़ी गारे से नहीं ढका हुआ पत्थर कच्चा छत है ... 1 घास / छाप्पर / बांस आदि 2 प्लास्टिक / पॉलिथिन	5	<20% = 5 20%-40%=4 41%-60%=3 61-80%=2 >80% =1

	3 हस्तनिर्मित टाइल्स		
26.	डाकघर / उप-डाकघर की उपलब्धता (हाँ-1;नहीं-2)	1	
27.	स्कूल की उपलब्धता (प्राथमिक -1; माध्यमिक स्कूल -2; हाई स्कूल -3; वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय -4; कोई स्कूल नहीं -5)	4	विकल्प 4 = 4 विकल्प 3=3 विकल्प 2=2 विकल्प 1 =1 विकल्प 5 =0
28.	व्यावसायिक शैक्षिक केंद्र / आईटीआई / आर सेटी / डीडीयू-जीकेवाई की उपलब्धता (हाँ-1;नहीं-2)	2	यदि हाँ
29.	उप केंद्र / पीएचसी / सीएचसी की उपलब्धता (पीएचसी -1; सीएचसी-2; उप केंद्र -3, कोई नहीं =4)	3	विकल्प 1,2,3=3 के लिए
30.	यदि गांव में उपलब्ध नहीं है; निकटतम स्थान की दूरी सीमा कोड जहां सुविधा उपलब्ध है; (<5 कि.मी. -1; 5-10 कि.मी. -2; > 10 कि.मी.-3)		<5कि.मी.- 2 5-10कि.मी.-1 >10कि.मी.-0
31.	पशु चिकित्सा क्लिनिक / अस्पताल की उपलब्धता (हाँ-1; नहीं -2)	2	If Yes
32.	यदि गांव में उपलब्ध नहीं है; निकटतम स्थान की दूरी सीमा कोड जहां सुविधा उपलब्ध है; (<5 कि.मी. -1; 5-10 कि.मी. -2; > 10 कि.मी.-3)		<5कि.मी.-1 >5कि.मी.-0
33.	निकास सुविधाकी उपलब्धता (बंध निकास - 1, खुला पक्का निकास जो टाईल स्लाब से ढका हुआ है - 2, कवर नहीं किया गया खुला पक्का निकास - 3, खुला कच्चा निकास - 4, कोई निकास नहीं - 5)	4	विकल्प 1=4 विकल्प 2 = 3, विकल्प 3 =2, विकल्प 4=1 विकल्प 5 = 0
आर्थिक विकास और आजीविका			
34.	मिट्टी परीक्षण केंद्रों की उपलब्धता (हां -1; नहीं -2)	2	यदि हाँ
35.	सरकारी बीज केंद्रों की उपलब्धता (हाँ -1, नहीं -2)	1	यदि हाँ
36.	उर्वरक दुकानों की उपलब्धता (हाँ -1; नहीं -2)	1	यदि हाँ
स्वास्थ्य, पोषण और स्वच्छता			
37.	सामुदायिक अपशिष्ट निपटान प्रणाली (हाँ -1, नहीं -2)	2	यदि हाँ
38.	सामुदायिक जैव गैस या उत्पादन उपयोग के लिए अपशिष्ट का रीसायकल (हाँ -1; नहीं -2)	3	यदि हाँ

39.	क्या गांव खुले में शौच से मुक्त है ? (ओडीएफ) (हाँ -1, नहीं -2)	3	यदि हाँ
40.	आंगनवाड़ी केंद्र की उपलब्धता (हाँ-1;नहीं-2)	1	यदि हाँ
41.	0-3 वर्ष के आयु वर्ग में कुल बच्चों की संख्या		
42.	आंगनवाड़ी के तहत पंजीकृत 0-3 साल की उम्र वाले बच्चों की संख्या	2	If >80%=2 60%-80%=1 <60%=0
	0-3 साल की उम्र के बच्चों की संख्या जिनका टीकाकरण हुआ है	3	>95% = 3(एमसीटीएस),91-95%=2 80-90%=1, अन्य 0
43.	आईसीडीएस रिकॉर्ड के अनुसार गैर-अवरूढ़ के रूप में वर्गीकृत बच्चों की संख्या	4	>90% = 4,81-90%=3 71-80%=2,60-70%=1 <60%=0
<b>महिला सशक्तिकरण</b>			
44.	एसएचजी में एकत्रित परिवारों की संख्या	3	यदि >80% =3, 51% - 80%=2,25% - 50%=1, <25%=0
45.	निर्माता समूह (पीजी) में एकत्रित परिवारों की संख्या	2	यदि >=25%=2, 10%-25%=1, अन्य 0
46.	ग्राम आधारित कृषि द्वारा समर्थित परिवारों की संख्या	1	यदि >=25% =1 अन्य 0
	विस्तार श्रमिक		
47.	ग्राम आधारित पशुधन द्वारा समर्थित परिवारों की संख्या	1	यदि >=25% =1 अन्य 0
	विस्तार श्रमिक		
<b>वित्तीय समावेशन</b>			
48.	एसएचजी की संख्या जिन्होंने बैंक ऋण का उपयोग किया है	3	यदि >=80%=3, यदि 51% से 80%=2, यदि 25% से 50% =1, <25%=0
<b>कुल</b>		<b>100</b>	